हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

वर्ष : 46 अंक : 38 गोंदिया, शुक्रवार दि. 10 जुलाई 2026 पृष्ठ : 04 मूल्य : 1.10 रू Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

खेत विवाद में वृद्ध की लाठी से पिटाई

गोंदिया : तिरोड़ा तहसील के खेडेपार गांव में खेत के विवाद को लेकर 70 वर्षीय वृद्ध किसान की दो लोगों द्वारा लाठी से बेरहमी से पिटाई की गई. जानकारी के अनुसार खेडेपार निवासी फिर्यादी मोतीराम रामलाल पटले (70) अपने खेत में खाद डालने का कार्य कर रहा था. इसी दौरान सपना गोविंदा मानकर (38) व दिवा सुकराम कटरे (45) वहां पहुंचे और गालीगलौज करते हुए लाठी से उसकी पिटाई कर दी. बीच-बचाव के लिए पहुंचे उसके पुत्र के साथ भी मारपीट कर धमकी दी गई. फिर्यादी की शिकायत पर तिरोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच सहायक फौजदार तिरपुडे कर रहे हैं.

संक्षिप्त

तिरोड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बने चामट

तिरोड़ा : महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में ब्लॉक अध्यक्षों की नई सूची की घोषणा की है और राजू चामट को गोंदिया जिले के तिरोड़ा ब्लॉक के ओबीसी सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. चामट की नियुक्ति के बाद तिरोड़ा तहसील कांग्रेस कमेटी, तहसील अध्यक्ष रमेश टेंभरे, हितेंद्र बावने, बीएलए ओम पटले, दिलीप ढाले, वनिता ठाकरे, पी.आर. पारधी ने उन्हें बधाई दी.

सड़कों की चौड़ाई बढ़ाए

आमगांव : ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की ओर जाने वाली सड़कें बहुत संकरी हैं. जिससे इन सड़कों पर आने-जाने वाले नागरिकों और वाहन चालकों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही कई लोग छोटे-बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं.

गुडमॉर्निंग टीम नदारद

सड़क अर्जुनी : तहसील के अन्य ग्रामों के लोग स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कई ग्रामीण घर में शौचालय होते हुए भी शौच के लिए बाहर जाते हैं. साथ ही शासन की शौचालय योजना का लाभलेकर अनेकों ने आधा अधूरा काम किया है. तहसील में खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई करने वाली गुडमॉर्निंग टीम नदारद हो गई है. प्रशासन व अधिकारियों का नियोजन शून्य होने की वजह से आज भी कई ग्रामों में शौचालयों का निर्माण कार्य होते हुए भी लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं.

निजी वाहन चालकों पर बेरोजगारी का साया

तिरोड़ा : एसटी बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रश. की छूट मिलने से महिलाओं का रुझान अब एसटी बस यात्रा की तरफ हो गया है. इस छूट के कारण शहर व गांव जाने वाले निजी वाहन काली-पीली, ऑटो व अन्य निजी बस चालकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. विशेष यह है कि एसटी बसों में 65 से 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहले से ही 50 प्रश. की छूट है. 75 वर्ष से ऊपर के अगले वरिष्ठ नागरिक को 100 प्रश. छूट और विकलांग लोगों को भी छूट से एसटी बस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. वहीं लालपरी को फिलहाल हाउसफुल के तौर पर देखा जा रहा है.

सड़कों की दयनीय अवस्था

सालेकसा : तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है. देवरी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें काफी हद तक जर्जर हैं. कई गांवों में जाने के लिए सड़क ही नहीं है. ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं.

राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन को शिक्षकों का समर्थन

खेतों में पानी भरा, किसानों पर दोबार बुआई की नौबत

संवाददाता / गोंदिया

जिला शिक्षक कृति महासंघ के नेतृत्व में 9 जुलाई को आयोजित राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन को जिले के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जोरदार समर्थन मिला. हजारों की संख्या में शिक्षकों ने आंदोलन में शामिल होकर सरकार की नीतियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की.

आंदोलन के दौरान शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष जमा हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया. इस ज्ञापन में 1 अप्रैल 2013 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी संबंधी न्यायालय के निर्णय को तत्काल लागू करने, शिक्षकों को बीएलओ एवं अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, शिक्षक मान्यता (संच मान्यता) से जुड़े कथित निर्णय वापस लेने, विद्यार्थियों के हित में शीघ्र नियमित शिक्षक भर्ती करने, सभी शिक्षकों को समान वेतन लागू करने तथा शिशु सेवक योजना समाप्त कर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की मांग की गई.

इस दौरान शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ शिक्षकों का नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों के भविष्य और स्कूलों के अस्तित्व को बचाने का संघर्ष है. उन्होंने सरकार से मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर में आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा. आंदोलन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ. इसमें जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. इस दौरान शिक्षकों की अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली.

आंदोलन में समन्वयक एस. यू. वंजारी, शिक्षक समिति के जिला अध्यक्ष संदीप तिड़के, विभागीय अध्यक्ष किशोर डोंगरवार, शिक्षक भारती के विभागीय अध्यक्ष प्रकाश ब्राह्मणकर, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ओ. एस. बिसेन, कास्ट्राईब संगठन के जिला अध्यक्ष संजय उके, पुरोगामी संगठन के जिला अध्यक्ष हरिराम येरणे, सुशील बंसोड, राज कड़व, जयेश लिल्हारे, संदीप मेश्राम, सुरेंद्र मैसारे, संतोष डोंगरे, अशोक बिसेन, ममता येडे, ममता चुटे, मीनाक्षी पंधरे समेत शिक्षक कृति महासंघ के कई पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित थे.

एग्रीस्टैंक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू

संवाददाता / गोंदिया

केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान की कृषि भूमि, फसलें और कृषि संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज की जा रही है।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पटवारी, कृषि विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से प्रत्यक्ष क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से मोबाइल ऐप द्वारा फसलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पहल से किसानों का एक डिजिटल कृषि डेटाबेस तैयार होगा और इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक शीघ्रता और पारदर्शिता से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

किसानों को मिलने वाले लाभ फसलों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड पंजीयन, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा नुकसान भरपाई और विभिन्न अनुदान योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्राप्त करने में सहायता, किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता में कमी, सरकार को सटीक कृषि जानकारी उपलब्ध होने से अधिक प्रभावी योजना बनाना, कृषि कर्ज, अनुदान और अन्य सेवाओं में पारदर्शिता में वृद्धि आदि लाभ है।

अंडरपास के स्थान पर फ्लाईओवर बनाने के लिए क्लेक्टर ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक कल

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया-चंद्रपुर रेलमार्ग पर भीमनगर क्षेत्र में निर्माणाधीन अंडरपास का कार्य रोककर उसके स्थान पर फ्लाईओवर (उड़ान पुल) बनाने की मांग को लेकर 11 जुलाई को सुबह 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है. इस बैठक में सांसद डॉ. प्रशांत पडोले, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरसेवक सुनील भरणे, स्नेहा (डॉली) गडपायले, सुनील भालेराव, अजय यादव, पंकज यादव, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग तथा रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

चारों ओर रेलवे फाटकों से घिरे कुंभारेनगर के नागरिक एक बार फिर अंडरपास निर्माण का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि यदि यहां दोबारा अंडरपास बनाया गया तो वार्ड क्रमांक 8 के कुंभारेनगर, सिग्नल टोली, भीमनगर, सावित्रीबाई फुले वार्ड और लक्ष्मीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों का जनजीवन प्रभावित होगा. साथ ही तिरोड़ा, मुंडीपार और ढाकनी क्षेत्र से आने जाने वाले लगभग 15 हजार लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

इसी मांग को लेकर 6 जुलाई को विधायक विनोद अग्रवाल, नगरसेवकों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अंडरपास के स्थान पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग की थी. ज्ञापन के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है. बैठक के दौरान रेलवे अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में नियत स्थल का निरीक्षण भी किया जाएगा.

फ्लाईओवर के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान का सर्वेक्षण करके आगे की कार्रवाई करके निर्णय लिया जाएगा. ज्ञापन के दौरान जिलाधिकारी मंदार पत्की ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल गोंदिया-चंद्रपुर रेलमार्ग पर चल रहे अंडरपास की खुदाई का कार्य रोक दिया जाएगा. लेकिन रेलवे लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का कार्य जारी रहेगा. अब शनिवार को होने वाली बैठक में इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय की दिशा तय होने की उम्मीद है.

700 मीटर दूरी से ही तेज रफ्तार वाहनों को कैमरे कर लेंगे कैच

आरटीओ ने शासन को भिजवाया प्रस्ताव

संवाददाता / गोंदिया

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही के कारण हाईस्पीड वाहनों से होनेवाली - दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब गोंदिया के उपप्रादेशिक - परिवहन विभाग की ओर से हाईस्पीड - वाहनों पर नजर रखने के लिए - सड़कों पर कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे इतने हाइटेक है कि 700 मीटर की दूरी से ही पता लगा लेंगे कि - कौनसा वाहन कितनी स्पीड से चल रहा है। कोई वाहन तेजी से चलता हुआ कैमरे में कैच हुआ तो तत्काल उसका चालान कट जाएगा। गौरतलब है कि जिले में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है, उनमें अधिकतर दुर्घटनाएं वाहनों के ओवर स्पीड से घटित हुई है। जिसमें अनेकों की जान भी चली गई तो कई लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए हैं। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब जिले के मुख्य मार्गों पर हाइटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे तेजी से दौड़नेवाले वाहनों पर नजर रखी जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवेगावबांध रोड पर खोबा बस स्थानक परिसरात, केशोरी फाटा, बाराभाटी, अर्जुनी बस स्थान, महागांव, कोहमारा-नागपुर रोड पर बोपाबोडी फाटा, कुंभली फाटा, लाखांदूर फाटा, पिंपलगांव शंकर पट बस स्थानक परिसर, कोहमारा - गोंदिया सड़क पर वडेगांव, भडंगा, गोरेगांव (दुर्गा चौक), कारंजा बायपास, फूलचुर नाका, देवरी गोंदिया सड़क के आमगांव चौक, मेहताखेडा फाटा, हरदोली, रामपुर, अंजोरा, बाम्हणी (रेल्वे फाटक), बोथली फाटा, आदासी (अग्रवाल कॉलेज), कलेक्टर ऑफीस चौक परिसर में यह कैमरे लगाए जाएंगे। अगर वाहन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक गति से चल रहे है तो तत्काल वाहन चालक के मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाएगा।

जनहित के बजाय ठेकेदारों को दी जा रही प्राथमिकता

केशोरी : केशोरी जिला परिषद क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में जिला परिषद सदस्य श्रीकांत घाटबांधे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी तथा विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक में खंड विकास अधिकारी पल्लवी वाडेकर, विस्तार अधिकारी गणेश माली, पंचायत समिति सदस्य घनश्याम धामट एवं फूलचंद बागडेरिया, ग्राम पंचायत प्रशासक नंदकुमार

गहाणे, विमुस अध्यक्ष अनिल लाडे, श्रीराम शेंडे तथा अरुण मस्के समेत अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत संत गाडगेबाबा और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई. बैठक में आंगनवाड़ी, विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, आवास, निर्माण और मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान कई गांवों में सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्य शुरु नहीं होने तथा कुछ कार्य अधूरे रहने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. शिक्षा विभाग में शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की गई. प्रधानमंत्री आवास एवं घरकुल योजनाओं की राशि मिलने में हो रही देरी पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलदा में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली गई. वहीं राजोली, भरनोली और इलदा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान तथा आंगनवाड़ी केंद्रों तक बिजली पहुंचाने पर भी चर्चा हुई.

बैठक के दौरान करांडली ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के स्थान पर अन्य कार्य को मंजूरी मिलने का मामला भी सामने आया. ग्रामीणों ने कुछ अधिकारियों पर जनहित की अपेक्षा ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. लेकिन, उन्होंने जिला परिषद सदस्य घाटबांधे द्वारा नियमित समीक्षा बैठक आयोजित कर विकास कार्यों की निगरानी किए जाने की सराहना की. बैठक का संचालन नितिन मेश्राम तथा आभार प्रदर्शन ग्राम विकास अधिकारी प्रेमानंद नगराले ने किया.

बीजेपार में छात्राओं क लिए नए छात्रावास का लोकार्पण

संवाददाता / सालेकसा

एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प योजना कार्यालय, आदिवासी विभाग देवरी के माध्यम से सालेकसा तहसील के बीजेपार स्थित शासकीय आदिवासी आश्रम विद्यालय में छात्राओं के नए छात्रावास का लोकार्पण, प्रवेश उत्सव एवं पालक मेळावा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकल्प योजना अधिकारी उमेद काशीद ने की। सरपंच मंगला कुंभरे ने लोकार्पण किया। विधायक संजय पुराम प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभापति वीणा कटरे, जिला परिषद सदस्य वंदना काले, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मेहतर वट्टी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन खांडेकर, सहायक प्रकल्प योजना अधिकारी सायली चिखलीकर, थानेदार विलास आडे, पूर्व उपसभापति दिलीप वाघमारे सहित अनेक

गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पूजन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत किया गया। विधायक संजय पुराम ने आदिवासी छात्र-छात्राओं से शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। उपस्थित सभी अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रस्तावना मुख्याध्यापक ए. के. इसकाबे ने रखी। संचालन एवं आभार प्रदर्शन डी. के. उरकुडे ने किया।

मुंडीकोटा गुजरी बाजार की वसूली में लाखों के भ्रष्टाचार का आरोप

जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग, सूचना के अधिकार से मिली जानकारी पर उठे सवाल

संवाददाता / तिरोड़ा

तहसील के मुंडीकोटा स्थित दैनिक गुजरी बाजार की वसूली में कथित तौर पर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने यह शिकायत तिरोड़ा के गटविकास अधिकारी, पंचायत समिति के सभापति तथा गोंदिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत की है। शिकायत के अनुसार, मुंडीकोटा ग्राम पंचायत ने पिछले तीन-चार वर्षों से दैनिक गुजरी बाजार की वसूली के लिए किसी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की। इसके बजाय ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के माध्यम से ही प्रतिदिन वसूली की जाती रही। आरोप है कि वास्तविक आय को कम दर्शाकर लाखों रुपये के राजस्व का गबन किया गया है। मुंडीकोटा क्षेत्र ग्रामीण अंचल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। नदी किनारे स्थित होने के कारण आसपास के गांवों के किसान प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सब्जियां, कृषि उपज तथा अन्य सामग्री बेचने के लिए यहां पहुंचते हैं। बाजार में प्रतिदिन लगभग 30 से 40 स्थायी एवं अस्थायी दुकानें लगती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक

दुकानदार से 10 रुपये वसूले जाते हैं। इस आधार पर प्रतिदिन लगभग 1,200 से 1,500 रुपये की वसूली होना स्वाभाविक माना जा रहा है। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में ग्राम पंचायत ने प्रतिदिन केवल 400 से 500 रुपये की वसूली दर्शाई है। इससे वास्तविक आय और अभिलेखों में दर्ज राशि के बीच बड़ा अंतर होने का संदेह उत्पन्न हुआ है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि अधिकांश दुकानदारों को वसूली की कोई अधिकृत रसीद नहीं दी जाती। केवल एक साधारण रजिस्टर में नाम दर्ज कर राशि वसूल की जाती है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के निर्धारित लेखा प्रारूपों में भी प्रतिदिन की वसूली का नियमित विवरण दर्ज नहीं किया गया, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका और गहरा गई. शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराएं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सरकारी राजस्व की संभावित हानि की भरपाई सुनिश्चित की जाए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी इस गंभीर शिकायत पर क्या रुख अपनाते हैं। यदि निष्पक्ष जांच होती है, तो मुंडीकोटा गुजरी बाजार की वसूली से जुड़े कथित लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का सच सामने आ सकता है।

'सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों में गुजरी बाजार की वसूली से संबंधित गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। उपलब्ध अभिलेखों और वास्तविक स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की आशंका प्रबल होती है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन और ग्राम पंचायत की आय में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मैंने सक्षम अधिकारियों से निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। यदि जांच में कोई अनियमितता या भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, तो संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।'

प्रकाश शिवराज मेश्राम, नागरिक, मुंडिकोटा

संपादकीय

सरकारी से मोहभंग

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग ८६ लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में ८८ लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल २०२३-२४ के २४.८ करोड़ से घटकर साल २०२५-२६ में २४.७२ करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर १२.७५ करोड़ से ११.८९ करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादतर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या १२,९५४ से घटकर ५,६६३ हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या १.११ लाख से घटकर १.०१ लाख हो गई है। दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या १.०३ करोड़ है, जिसके चलते छात्र-शिक्षक अनुपात २५ से घटकर २४ हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर ४८.४ होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर दावों की हकीकत तार्किक कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सही मायने में किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के नीति-नियंताओं को समझना चाहिए कि समाज में जिस वर्ग को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, वही सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपनी मजबूरी के चलते सरकारी स्कूलों की ओर रुख करता है। इसके बावजूद कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गाहे-बगाहे सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर बच्चे को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा था तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में शिक्षा के ये लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किए गए? यदि तब केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये ईमानदार प्रयास किए होते और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये होते तो आज लोगों को सरकारी स्कूलों से मोहभंग न हो रहा होता। यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे-बगाहे गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से स्थितियां विकट हुई हैं। यह विडंबना ही कही जाएगी कि सत्तर के दशक में शिक्षा के उन्नयन के लिये गठित कोठारी आयोग की वह सिफारिश आज भी धूल फांक रही है, जिसमें शिक्षा पर देश के जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया था। आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व साख पर आंच आई है।

धानोरकर ने वडेट्टीवार को कहा 'बाहरी', हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

महानगरपालिका को लेकर कांग्रेस में चल रहा बवाल जारी : चंद्रपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं एक्जिट हो जाऊंगी

संवाददाता । चंद्रपुर

चंद्रपुर महानगरपालिका को लेकर कांग्रेस में चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुट नेता को लेकर पार्टी में छिड़ा महाभारत अब सांसद प्रतिभा धानोरकर तथा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया है. मामला इतना गंभीर हो गया है कि सांसद धानोरकर ने विधायक वडेट्टीवार को चुनौती देते हुए कह डाला है कि मेरे क्षेत्र में 'बाहरी' (ब्रह्मपुरी से विधायक विजय वडेट्टीवार) व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है. अगर उनमें हिम्मत है तो चंद्रपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ कर दिखाएं. मैं एक्जिट हो जाऊंगी. मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगी. चंद्रपुर महानगरपालिका में कांग्रेस का तथा मेरे ही गुट का गुट नेता होगा, क्योंकि बहुमत

हमारे पास ही है. सांसद धानोरकर ने गुरुवार को अपने समर्थक पार्षदों की विभागीय आयुक्त के पास पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए यह प्रतिक्रिया दी.

विदित हो कि कांग्रेस के गुट नेता चयन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए गुरुवार का समय दिया था. इसके बाद धानोरकर गुट के चंद्रपुर महानगरपालिका के 16 पार्षदों ने आज उपस्थित रह कर 'हम साथ-साथ है' का प्रदर्शन किया. दूसरी ओर विधायक वडेट्टीवार गुट के पास 11 पार्षद ही बचे है.

इस तरह रहा है अब तक का घटनाक्रम

ज्ञात कि विभागीय आयुक्त के गुट नेता संबंधी पहले के फैसले के बाद दोनों गुटों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विभागीय आयुक्त को सभी पक्षों और पार्षदों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लेने तथा तत्संबंधी रपट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे. इसके मद्देनजर गुरुवार को पार्षदों की परेड विभागीय आयुक्त के पास कराई गई, जिसमें धानोरकर गुट का पलड़ा भारी रहा. अब देखना यह होगा कि सोमवार तक क्या कोई चमत्कार होता है या फिर धानोरकर गुट का वर्चस्व बना रहता है.

जिससे गुरुवार को वडेट्टीवार गुट के मनपा में गुट नेता राजेश अडूर अपने वकील के साथ पेश हुए. उन्होंने सोमवार तक का समय मांगा. इसके बाद विभागीय आयुक्त ने अंतिम अवसर के तौर पर सोमवार का वक्त देने की जानकारी सूत्रों ने दी.

धानोरकर गुट के 16 पार्षद हाजिर, वडेट्टीवार गुट के अडूर रहे उपस्थित

इससे पहले हुई सुनवाई में सांसद प्रतिभा धानोरकर गुट के सभी 16 पार्षद विभागीय आयुक्त कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे. विभागीय आयुक्त के सामने परेड कर एकता दिखाई. दूसरी ओर, विजय वडेट्टीवार गुट का कोई भी पार्षद सुनवाई में शामिल नहीं हुआ. उनकी तरफ से केवल गुट नेता राजेश अडूर और अधिवक्ता विभागीय आयुक्त के सामने पेश हुए.

हीरा स्वीट में मरा हुआ चूहा मिलने पर लाइसेंस रद्द

उत्पादन और बिक्री पूरी तरह बंद, एफडीए की कार्रवाई

संवाददाता । नागपुर

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पाचपावली स्थित हीरा स्वीट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका खाद्य व्यवसाय लाइसेंस रद्द कर दिया है. उत्पादन इकाई में निरीक्षण के दौरान मृत चूहा मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. एफडीए के इस कदम से शहर के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के अनुसार, एफडीए की टीम ने 3 जुलाई को हीरा स्वीट की उत्पादन इकाई का औचक निरीक्षण किया था. जांच के दौरान उत्पादन क्षेत्र में एक मृत चूहा मिला, जिसे खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना गया. निरीक्षण के बाद विभाग ने प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की और विस्तृत जांच की गई.

जांच में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर एफडीए ने हीरा स्वीट का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया. लाइसेंस निरस्त होने के साथ ही प्रतिष्ठान में मिठाइयों के उत्पादन और बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

उल्लंघन करने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

एफडीए की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी सतर्कता बढ़ गई है. विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से स्वच्छता मानकों और खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके.

गटर-नालों की सफाई तत्काल करें

मानसून के बीच महापौर ठाकरे ने दिए अधिकारियों को निर्देश

संवाददाता । नागपुर

नागपुर शहर में विलंब से मानसून पहुंचा. ऐसे में मनपा के पास सुनहरा मौका था कि मानसून से जुड़े नदी-नालों, सीवरलाइन की साफ-सफाई पूरी कर लें. लेकिन हालत यह है कि अभी भी शहर के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी तैयारी अधूरी है. मानसूनी फुहारों के बीच मंगलवार को महापौर नीता ठाकरे ने हनुमाननगर और धंतोली जोन में बैठक लेकर सीवरलाइन, नालों की सफाई का काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा जोन में पार्षदों की समस्याओं को सुनते हुए अतिक्रमण हटाने, खुले चेंबर को दुरुस्त करने, कार्य स्थल की बैरिकेडिंग करने आदि के निर्देश भी दिए.

बैठक में उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दाणी, सभापति ज्योति देवघरे, भारती बुंदे, अतिरिक्त आयुक्त श्री अंकित, उपायुक्त राजेश भगत, मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले आदि उपस्थित थे.

बैठक के दौरान हनुमान नगर जोन के पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं से महापौर को अवगत कराया. उन्होंने मुख्य रूप से अतिक्रमण, अवैध बाजारों तथा यातायात जाम की समस्या उठाई. पार्षदों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए, ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो सके. उन्होंने यह भी बताया कि कई स्थानों पर लगने वाले अवैध बाजारों के कारण यातायात प्रभावित होता है तथा बाजार समाप्त होने के बाद वहां फैला कचरा दुर्गंध का कारण बनता है.

दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत

नागपुर : हिंगना थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई. पहली दुर्घटना 8 जुलाई की रात करीब 7.30 बजे मोंढा क्षेत्र में भारत पेट्रोल पंप के पास हुई. मोंढा निवासी 45 वर्षीय किशोर मधुकर राखूंड़े भोजन के बाद पैदल टहल रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात बस ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे के बाद बस चालक घटना स्थल से फरार हो गया.

गंभीर रूप से घायल राखूंड़े को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 9 जुलाई गुरुवार की सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में उपनिरीक्षक रोकड़े जांच कर रहे हैं. दूसरा दुर्घटना गुरुवार 9 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे जामठा चौक के सामने हुई. बैतूल निवासी तथा वर्तमान में बुटीबोरी में रहने वाले 29 वर्षीय सुदामा पंजू विश्वकर्मा अपनी बाइक से जा रहे थे.

कोरची का शराब विक्रेता छह महीने के लिए तड़ीपार

गढ़चिरोली : जिले में शराब बेचने और ले जाने की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. जिससे इन मामलों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने कार्रवाई करते हुए कोरची के ग्राम खुर्शीपार निवासी शराब विक्रेता तिलक उंदीरवाड़े को छह माह के लिए तड़ीपार करने का आदेश जारी किया है. कोरची के तिलक उंदीरवाड़े के खिलाफ अवैध शराब बिक्री, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून व सुव्यवस्था को बाधित करने तथा अन्य गंभीर प्रकार के विभिन्न अपराध के २००९ से २०२५ तक मद्य निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत १२ मामले दर्ज हैं. उसमें अबतक कोई बदलाव न दिखने से कोरची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उपविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी कुरखेड़ा के पास जिले से तड़ीपार करने का प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव के संबंध में जांच करके आरोपी को जिले की सीमा से छह महीनों के लिए तड़ीपार करने का आदेश दिया गया. तड़ीपार के आदेश का उल्लंघन करने पर उसे गिरफ्तार करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पत्नी के वियोग में दो दिन बाद पति ने भी तोड़ा दम

भद्रावती : भद्रावती के गवराला क्षेत्र में एक मर्मस्पर्शी घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. जीवनभर सुख-दुख के साथी रहे येरकाडे दंपति दो दिनों के अंतराल में दुनिया को अलविदा कह दिया. मिली जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई को लता येरकाडे (52) का आकस्मिक निधन हो गया.

6 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार किया गया. परिजनों और परिचितों ने अभी इस सदमे से उबरना भी शुरू नहीं किया था कि 7 जुलाई को उनके पति बंडू येरकाडे (62) ने भी अंतिम सांस लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया.

बताया जाता है कि बंडू येरकाडे लंबे समय से लकवे से पीड़ित थे. उनकी पत्नी लता येरकाडे पूरे समर्पण और सेवा-भाव से उनकी देखभाल करती थीं. दवाइयों से लेकर दैनिक जरूरतों तक, हर पल वह उनके साथ खड़ी रहीं. पत्नी के अचानक निधन का गहरा आघात बंडू येरकाडे सहन नहीं कर सके और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गए. आखिरकार, उन्होंने भी पत्नी के वियोग में दम तोड़ दिया. येरकाडे दंपति के असामयिक निधन से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्षेत्र के लोगों ने इसे सच्चे जीवनसाथी के अटूट प्रेम और साथ की मार्मिक मिसाल बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की.

वाहनों का आवागमन आलापल्ली से मंचेरियल मार्ग से होगा

सिरोंचा-आलापल्ली मार्ग पर 31 अक्तूबर तक भारी वाहनों पर रोक, प्रशासन का फैसला

गढ़चिरोली : राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353-सी पर सिरोंचा-आलापल्ली मार्ग पर चल रहे राजमार्ग के निर्माण कार्य और मानसून के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस मार्ग पर सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन पर 7 जुलाई की रात से 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध लगाया गया है. जिससे जिले के दक्षिण भाग से गुजरने वाले भारी वाहन अब आलापल्ली से सिरोंचा, मंचेरियल-राजुरा होते हुए चंद्रपुर से गढ़चिरोली पहुंचेंगे.

इस संदर्भ में जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अविश्यांत पंडा ने यह आदेश मंगलवार, 7 जुलाई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धाराओं के तहत आदेश जारी किया है. लेकिन, आपातकालीन सेवाएं, यात्री बसें, पानी की आपूर्ति, पुलिस, खाद्य व दवा की आपूर्ति, महावितरण, दूरसंचार, स्वास्थ्य विभाग तथा सड़क मरम्मत से जुड़े वाहनों को इस आदेश से बाहर रखा गया है. गौरतलब है कि बारिश और सड़क के निर्माण कार्य के चलते सिरोंचा से आलापल्ली और आलापल्ली से आष्टी तक यातायात प्रभावित होने के साथ अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं. सड़क की बदहाली के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका शैक्षणिक नुकसान हो रहा है तो इस सड़क से पैदल जाना भी अब मुश्किल हो गया है. इस कारण प्रशासन ने यह आदेश जारी करने के साथ ही आलापल्ली-आष्टी-बल्लारपुर-मंचेरियल वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने दिए हैं.

तलाक के छह महीने बाद महिला ने की आत्महत्या

संवाददाता । नागपुर

मानकापुर थाने के तहत एक 38 वर्षीय महिला ने अवसाद के चलते अपने घर के बेडरूम में फंदे से लटककर फांसी लगा ली. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छह महीने पहले हुए तलाक के बाद वह मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी. मृतक जूना मानकापुर स्थित समता चौक, आंबेडकर मार्ग स्थित पूजा रेसिडेंसी निवासी मीनल महेंद्र धोंगले (38) है.

बताया जाता है कि पारिवारिक तनाव और वैवाहिक जीवन टूटने से मीनल अवसादग्रस्त हो गई थी. मृतका ने आत्महत्या से पहले अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए लगाए गए ब्लैकबोर्ड पर अंग्रेजी में 'मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं' लिखकर अपनी अंतिम भावनाएं व्यक्त की है. विवाह के कुछ वर्षों बाद से ही उनके पति के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे.

पिछले दो वर्षों से पूजा रेसिडेंसी क्षेत्र में अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं. वह करीब छह महीने पहले हुए तलाक के बाद से वह तनाव से गुजर रही थीं. उनकी 11 वर्षीय बेटी उनके साथ ही रहती थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अस्पताल में भर्ती थी बेटी : मीनल की 11 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती थी. बच्ची के लिए भोजन लेकर मीनल के माता-पिता अस्पताल गए थे. दोपहर करीब दो बजे जब माता-पिता घर लौटे तो अंदर से दरवाजा बंद मिला. काफी देर तक घंटी बजाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया. इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है.

जंगल में गए युवक की बाघ के हमले में मौत

ब्रह्मपुरी: ब्रह्मपुरी तहसील के दक्षिण वन परिक्षेत्र के भुज उपक्षेत्र अंतर्गत पद्मापुर नियत क्षेत्र में गुरुवार, 9 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे पद्मापुर चक जंगल से सटे कुरण गट क्रमांक 21 में जंगली साग (रानभाजी) तोड़ने गए अनिल दिवटे (30, बल्लारपुर) की बाघ के हमले में मौत हो गई. अनिल के जंगल से लगे कुरण क्षेत्र में जंगली साग एकत्र करने के दौरान झाड़ियों में छिपे बाघ के हमला करने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

वन विभाग तथा पुलिस प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा किया. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल, ब्रह्मपुरी भेज दिया गया. इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वन विभाग ने एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्र में हिंसक वन्यजीव की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे तथा लाइव कैमरे लगाए हैं. जंगल और उससे सटे इलाकों में वन कर्मियों की नियमित गश्त बढ़ा दी गई है. ब्रह्मपुरी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस दौरान घटनास्थल का दौरा किया. पंचनामा करने के दौरान सहायक वन संरक्षक (प्रादेशिक एवं वन्यजीव) एम. बी. गायकवाड, दक्षिण ब्रह्मपुरी के वनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. वी. सोनडव आदि उपस्थित थे.

दो साल से खुले में पड़ा धान, आखिर बरसात में शुरू हुआ उठाव

एटापल्ली : तहसील के जारावंडी स्थित आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था में किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान पिछले दो वर्षों से खुले में पड़ा है. समय पर उठाए नहीं जाने से तेज धूप और बारिश में धान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा. अब बरसात के बीच जल्दबाजी में धान की नीलामी के बाद उसका उठाव शुरू किया गया है.

क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि खुले में पड़े करीब 80 से 90 प्रतिशत धान की गुणवत्ता खराब हो चुकी है. गुरुवार, 9 जुलाई को धान से लदा एक ट्रक परिवहन के दौरान कीचड़ में फंस गया. ट्रक बाहर निकालने के लिए उसमें रखा धान सड़क और कीचड़ में उतार दिया गया. इससे बड़ी मात्रा में धान बर्बाद हो गया. घटनास्थल पर धान सड़क पर बिखरा हुआ दिखाई दिया. इस घटना से स्थानीय किसानों और

धूप और बारिश में धान की गुणवत्ता खराब हुई, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

नागरिकों में भारी नाराजगी है. किसानों का कहना है कि समय रहते धान का भंडारण या परिवहन किया जाता तो हजारों क्विंटल धान खराब होने से बच सकता था. इसके विपरीत अब बरसात के बीच जल्दबाजी में धान की नीलामी कर उसका उठाव शुरू किया गया है.

लगातार बारिश के कारण पहले ही बड़ी मात्रा में धान की गुणवत्ता प्रभावित हो चुकी है. वहीं परिवहन के दौरान भी धान की बर्बादी हो रही है. इससे किसानों में आक्रोश है. उनका आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा नुकसान के मुआवजे की मांग की है.

सिर पर टोपी और हाथ में मंजीरा कांग्रेस भी बोली, 'जय श्रीराम'!

अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी के विरोध में 'रघुपति राघव राजाराम' सत्याग्रह

नागपुर : अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है. इसमें चौकीदार ही चोर होने का आरोप लगाते हुए नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर में 'रघुपति राघव राजाराम' सत्याग्रह आंदोलन किया. सिर पर सफेद टोपी और हाथ में मंजीरे लेकर 'रघुपति राघव राजाराम' भजन गाते हुए कांग्रेस ने श्रीराम का जयघोष किया.

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुड़धे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सचिव नितिन कुंभलकर, प्रवक्ता अतुल लोंढे, प्रदेश सचिव सुरेश जग?यासी, नयना झाड़े, विजय सरटकर, बंटी शेलके, आकाश तायवाड़े सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह आंदोलन हुआ. कार्यकर्ताओं

ने पोद्दारेश्वर राम मंदिर की सीढ़ियों के सामने धरना दिया और मृदंग व मंजीरों की थाप पर 'रघुपति राघव राजाराम' भजन, 'खरा तो एकचि धर्म' और 'पसायदान' का सामूहिक गायन किया.

कार्यकर्ताओं ने 'भगवान को लूटा, देश को लूटा, अब भक्तों का संयम टूटा', 'राम के नाम पर वोट मांगते हो, तो चंदे का हिसाब क्यों छुपाते हो?', 'राम हमारे मन में, राम हमारे संविधान में', ऐसे बैनर लहराकर प्रभु के नाम पर हो रही राजनीति और चंदा चोरी पर सवाल उठाए. इसके बाद सभी ने प्रभु श्रीराम के दर्शन किए और प्रार्थना की कि प्रभु श्रीराम के नाम पर पैसे खाने वालों को सद्बुद्धि दे. इसके बाद गणेशपेठ पुलिस थाने पहुंचकर चंदा चोरी मामले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा गया.

आंदोलन में नगरसेवक दीपक पटेल, सुहास नाटवटकर, पृथ्वी मोटघरे, कुमुदिनी गुड़धे, प्रशांत ढाकणे, दुर्गेश प्रधान, दिनेश तराले, अधि. अभय रणदिवे, मोतीराम मोहाड़ीकर, राहुल अभंग, चंदू वाकोड़कर, बाबा शेलके, कुणाल निमगड़े, रमेश ठाकरे, कमलेश लारोकर, रिजवान अंसारी, महेश श्रीवास, प्रकाश साळुंके, कुणाल मौदेकर, डॉ. प्रकाश ठगे, मेहुल अडवानी, अभिषेक ठाकरे, जुल्फिकार भुट्टो, ममता तोमर, विजय तिवारी, नसीम अनवर, अनिल मछले, अशोक निखाड़े, चंद्रकांत बड़गे, नरेश खड़से, गोपाल पट्टम, हेमंत चौधरी, मुकेश शर्मा, चंद्रकांत हिंगे, रीमा चव्हाण, साधना बोरकर, मनोज चवरे आदि ने भाग लिया.

चोरों पर कार्रवाई करें : गुड़धे

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान कोष में बड़ा गबन हुआ है. इस मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही श्रीराम भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात करने वाले संबंधित लोगों को सजा मिलनी चाहिए, यह मांग कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रफुल्ल गुड़धे ने की.

हैंडपंप का खारा पानी पीने को मजबूर लोग

शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता । मांडगांव

ग्राम पंचायत मांडगांव के ग्रामीण पिछले करीब दो माह से श्मशान भूमि स्थित हैंडपं से आपूर्ति किए जा रहे खारे (क्षारयुक्त) पानी के कारण गंभीर परेशानी झेल रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह पानी पीने, भोजन बनाने और दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है तथा इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है. विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें की गईं, लेकिन

अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. उनका आरोप है कि संबंधित प्रशासन और विद्युत ठेकेदार बार-बार दो दिन में समस्या दूर करने की बात कहते रहे, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. बताया गया कि नई जलापूर्ति योजना का कार्य बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण रुका हुआ है. टंकी निर्माण से जुड़े ठेकेदार का कहना है कि विद्युत कनेक्शन मिलते ही मोटर चालू कर नदी स्रोत से नियमित जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से लोगों को

समस्या हल न होने पर होगा लोक तांत्रिक तरीके से आंदोलन

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो वे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों से शिकायत करेंगे. इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा. साथ ही खारे पानी के कारण किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य को नुकसान होने पर संबंधित प्रशासन और विद्युत ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

असुरक्षित एवं खारा पानी उपलब्ध कराना उचित नहीं है. स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारी है.

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पानी की गुणवत्ता जांच का जो प्रतिवेदन दिखाया गया, वह श्मशान भूमि के बोरवेल का नहीं बल्कि कुएं के पानी का था. ऐसे में खारे पानी का वास्तविक कारण क्या है, इसकी निष्पक्ष जांच कर स्थायी समाधान किया जाए. ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक नई जलापूर्ति व्यवस्था शुरू नहीं होती, तब तक वैकल्पिक रूप से कुएं का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए तथा जलापूर्ति योजना को शीघ्र शुरू करने के लिए विद्युत लाइन का कार्य तेजी से पूरा कराया जाए.

इस संबंध में ग्रामसेवक डेहनकर ने ग्रामीणों को दूरभाष पर जानकारी दी कि श्मशान भूमि के बोरवेल से जलापूर्ति बंद कर अगले दिन से कुएं से पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा तथा वणा नदी स्रोत से नियमित जलापूर्ति शुरू करने के लिए विद्युत लाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा. ज्ञापन देते समय पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुनील डुकरे, भूषण चंदनखेडे, विक्री घुसे, लिलेश्वर वरवटकर, महेश लांडगे, अमोल कुंभलकर, किशोर मेंढे, योगेश पाहुणे, वनिता उईके, कुसुम वानखेडे, शालु येनुरकर, निर्मला डोंगरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित थीं.

पवन लॉज में देह व्यवसाय का भंडाफोड

संवाददाता । वर्धा

गुप्त सूचना के आधार पर अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंधक कक्ष (एएचटीयू) एवं स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) की संयुक्त टीम ने शहर के भामटीपुरा स्थित पवन लॉज पर छापेमारी कर देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक महिला को मुक्त कराया तथा लॉज संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस को सूचना मिली थी कि पवन लॉज में जिले के बाहर से महिलाओं और युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है. सूचना की पुष्टि के लिए 8 जुलाई को पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक को लॉज में भेजा. सूचना सही पाए जाने पर पुलिस टीम ने तत्काल छापा मारकर एक महिला को वहां से मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लॉज संचालक सचिन हरिश जाधव (45), निवासी भामटीपुरा, वर्धा को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अप्पर पुलिस अधीक्षक अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, अप्पर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी, सहा. पुलिस निरीक्षक माधुरी वाघाडे, पुलिस उपनिरीक्षक वर्षा तांदुलकर, पुलिस अंमलदार अमर लाखे, संजयसिंग सुर्यवंशी, चंद्रकांत बुरंगे, संजय राठोड, धर्मेंद्र अकाली, नवनाथ मुंडे, अक्षया सावरडकर, सोनाली मेसरे, प्रतिक्षा पेंदाम तथा एएचटीयु व अपराध शाखा की टीम ने की.

गोवंश प्रजनन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन गंभीर

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

संवाददाता । वर्धा

गाय-भैंसों की नस्ल सुधार और प्रजनन प्रक्रिया को वैज्ञानिक एवं कानूनी रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू 'महाराष्ट्र गोवंश प्रजनन (विनियमन) अधिनियम-2023' का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय विभाग ने सभी निजी कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन) केंद्रों, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रों, प्रशिक्षण संस्थानों तथा की अपील की है. विभाग ने स्पष्ट किया है सेवा प्रदाताओं से तत्काल पंजीकरण कराने कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पशुसंवर्धन एवं दुग्ध व्यवसाय विभाग के उप आयुक्त डॉ. जगदीश बुकतरे ने बताया कि यह अधिनियम राज्य में 5 दिसंबर 2024 से लागू है. इसका उद्देश्य

उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के वीर्य का उपयोग कर दुग्ध देने वाले पशुओं की बेहतर नस्ल तैयार करना तथा प्रजनन प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाना है. उन्होंने कहा कि अभी भी कई निजी कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदाताओं ने पंजीकरण नहीं कराया है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटिल ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अधिनियम के तहत सभी कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रों, प्रशिक्षण संस्थानों और सेवा प्रदाताओं का 'महाराष्ट्र गोवंश प्रजनन नियमन प्राधिकरण' में पंजीकरण अनिवार्य है. प्राधिकरण को ऐसे केंद्रों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा अवैध सामग्री जब्त करने के विशेष अधिकार भी दिए गए हैं. विभाग के अनुसार निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रमाणपत्रधारकों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बिना पंजीकरण के प्रजनन कार्य करने अथवा अनधिकृत जमे हुए वीर्य (फ्रोजन सीमेन) का उपयोग करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं सेवाओं के संबंध में भ्रामक विज्ञापन या गलत प्रचार करने पर 6 महीने तक की जेल, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है.

उच्च प्राथमिक विद्यालय पांजरा में हुआ प्रवेशोत्सव

संवाददाता । तिरोड़ा

जिप उच्च प्राथमिक विद्यालय पांजरा, केंद्र मुंडीकोटा में शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ. पहली कक्षा में नामांकित सभी 12 में से 12 पात्र बच्चों को सत्र के पहले ही दिन स्कूल में प्रवेश दिया गया. स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्यालय पांजरा के परिसर से रंगलाल पटले द्वारा सजाई गई एक बैलगाड़ी को लेजिम और बैंड के साथ स्कूल के प्रवेश द्वार पर रखा गया था. मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में सदस्य प्रीति चामट, रीना चामट, रंगलाल पटले और माता-पिता उपस्थित थे. उन्होंने प्रवेशोत्सव पर बच्चों के पैरों के निशान लिए और उनका मुंह मीठा कराया. कार्यक्रम की शुरुआत क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया गया. स्कूल के पहले दिन, सभी विद्यार्थियों को गणवेश व किताबें दी गई.

मरम्मत करने की किसानों की मांग

संवाददाता । कुरखेडा

तहसील के खरमतटोला के जवराबोडी तालाब में विगत 2 से 3 वर्षों से मलबा व गाद जमा होने से तालाब का जल निकासी द्वार बंद हुआ है. जिससे तालाब के पानी का खेती के लिए उचित उपयोग नहीं हो रहा है. परिसर के किसानों के समक्ष सिंचाई की गंभीर निर्माण हुई है. इस संदर्भ में किसानों ने भाजपा तहसील अध्यक्ष चांगदेव फाये की ओर समस्या बताने के बाद उन्होने ग्राम पंचायत के पदाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ तालाब का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जिससे इस उद्देश से इस तालाब की निर्मिती की थी. लेकिन तालाब का जल निकासी द्वार गाद के कारण बंद हुआ है. तालाब का पानी किसानों तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों को व्यापक दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. निरीक्षण के दौरान उपविभागीय अभियंता मरसकोल्हे, ग्रामपंचायत सरपंच विजय तुलावी, ग्रामपंचायत सदस्य राकेश तुलावी, विनोद नागपुरकर, शेतकरी प्रकाश बोडखे, अरुण लंजे, गुणाजी मडावी, रोजगार सेवक दिलीप वैरागडे, गजानन दरवडे, पंढरी

दादगाये, किसन नैताम, शामराव नैताम, जीवन ठलाल, चारू पटणे तथा बडी संख्या में किसान उपस्थित थे. इस दौरान संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या पर तत्काल हल निकालने संदर्भ में विचारविनिमय किया गया.

उक्त जवराबोडी तालाब परिसर में करीब 150 से 200 किसानों के लिए व्यापक महत्वपूर्ण है. सैकडों एकड खेती की सिंचाई इस तालाब पर निर्भर है. जिससे जल निकासी द्वार की तत्काल मरम्मत कर पानी का सुचारू प्रवाह शुरू करे, ऐसी मांग किसानों ने की है. इस संदर्भ में किसानों ने संबंधित प्रशासन से ज्ञापन सौंपा है. इस समय ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने सकारात्मक भूमिका लेते हुए ग्रामपंचायत में उपलब्ध निधि से अस्थायी स्वरूप में मरम्मत का आश्वासन दिया. जिससे किसानों को कुछ राहत मिलनेवाली है. वहीं भविष्य में ऐसी समस्या निर्माण न हो इसके लिए जवराबोडी तालाब पर नया गेट व कायमस्वरूपी जल निकासी द्वार निर्माझा करने सरकार विशेष निधि मंजूर करे, ऐसी मांग भाजपा तहसील अध्यक्ष चांगदेव फाये समेत पदाधिकारियों ने की है.

आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया आंदोलन

देसाईगंज : आंगणवाड़ी सेविका और मतदनीस का कोरोना काल का बकाया भत्ता देने की मांग को लेकर आयटक के नेतृत्व में आंगनवाडी सेविका और मतदनीस ने आयटक के देवराव चवले के नेतृत्व में पंचायत समिति कार्यालय के सामने आंदोलन किया. वहीं बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बकाया भत्ता देने की मांग की है. आंदोलनकर्ता आंगनवाडी कर्मियों ने कहां कि, कोरोना कालावधि में आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घर-घर में पहुंचकर विभिन्न तरह की सेवा देने का काम किया. सरकार की सूचना और निर्देश का पालन करने के बाद भी सरकार द्वारा घोषित किये गये प्रति माह 1 हजार रूपये भत्ता संबंधित कर्मचारियों को नहीं दिया गया है. विशेषतः इस संदर्भ में अनेक बार सरकार और प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी अब तक कोरोना भत्ता नहीं मिला है. जिससे आंगणवाडी कर्मियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है. आंगनवाडी कर्मियों को होनेवाली परेशानियों को गंभीरता से लेकर तत्काल कोरोना कालावधि का बकाया भत्ता दे, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी आंदोलनकर्ताओं ने दी है. जिसके बाद गुटविकास अधिकारी ने ग्रापं स्तर से आंगनवाडी कर्मचारियों को बकाया कोरोना भत्ता देने संदर्भ में पत्र संगठन को दिया. जिसके बाद आंदोलनकर्ताओं ने समाधान व्यक्त कर अपना अनशन समाप्त किया. आंदोलन में रोहिदास फुलझले, चुन्नीलाल मोटघरे, सचिन जंबेवार, वैशाली गोंडाने, लिना गेडाम, निशा लांजेवार, सुवर्णा तितिरमार समेत बडी संख्या में आंगणवाडी कर्मी उपस्थित थे.

बारिश में निर्माण सामग्री से परेशानी

गोंदिया : नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य करते समय निर्माण सामग्री स्वयं की मालकियत की जगह पर रखी जानी चाहिए. लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि निर्माण सामग्री निर्माण कार्यस्थल के पास सड़कों पर ही रख दी जाती है. जिससे कई बार आवागमन में भी बाधा निर्माण होती है. सड़क पर सामग्री रखने के कारण न केवल आवागमन में बाधा निर्माण होती है, बल्कि सड़क के किनारे बनी नालियां भी चोक हो जाती है. अभी बारिश के दिनों में कीचड से फिसलन होती है.

छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू

हिंदी विवि में शैक्षणिक मांगों को लेकर आंदोलन, शोधार्थी भी हुए शामिल

संवाददाता । वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के छात्र-छात्राओं एवं शोधार्थियों ने अपनी विभिन्न शैक्षणिक मांगों को लेकर बुधवार से प्रशासनिक भवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया. छात्रों का कहना है कि आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, शोध संस्कृति और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों

को लेकर है.

छात्रों की प्रमुख मांगों में वर्ष 2022 से बंद पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पुनः शुरू करना, स्त्री अध्ययन विभाग और फिल्म अध्ययन विभाग को वर्धा मुख्य परिसर में फिर से संचालित करना तथा पूर्व में बंद किए गए डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दोबारा प्रारंभकरना शामिल है. छात्रों का आरोप है कि इन मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन और आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. छात्रों का कहना है कि पीएचडी प्रवेश बंद रहने से शोध कार्य प्रभावित हुआ है, जबकि स्त्री अध्ययन एवं फिल्म अध्ययन विभागों के मुख्य परिसर से हटने से अकादमिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के अवसरों पर असर पड़ा है. उनका यह भी कहना है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम बंद होने से कौशल आधारित और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर कम हुए हैं. छात्रों ने मांग की है कि उनकी सभी मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन समयबद्ध और लिखित निर्णय सार्वजनिक करे. उनका कहना है कि सकारात्मक निर्णय होने तक सत्याग्रह जारी रहेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

किसानों के खेतों में पहुंचे कृषि वैज्ञानिक

खेती की नई तकनीक की दी गई जानकारी

वर्धा : कृषि दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र सैलसुरा की ओर से कृषि संजीवनी सप्ताह का आयोजन किया गया. इस दौरान वैज्ञानिकों ने गांव-गांव जाकर किसानों के खेतों का निरीक्षण किया. खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान बताए. यह कार्यक्रम हिंगनघाट, वर्धा, देवली तहसील के कई गांवों में आयोजित हुआ.

विशेषज्ञों ने खरीफ फसलों के बेहतर प्रबंधन, जल संरक्षण और बदलते मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी. वैज्ञानिकों ने सोयाबीन, कपास, तुअर की पोषण व्यवस्था, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी. किसानों को बारिश के मौसम में पशुओं की देखभाल, समय पर टीकाकरण का महत्व भी समझाया गया.

कार्यक्रम में चौड़ी मेड़-सरी पद्धति से बुआई, जल निकासी, कुक्कुटपालन, डेयरी व्यवसाय और घर की पोषण वाटिका विकसित करने पर भी मार्गदर्शन किया गया. कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों का दौरा कर फसलों की स्थिति देखी व आवश्यक उपाय सुझाए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.

62 बच्चों की होगी हार्ट सर्जरी

संवाददाता / गड़चिरोली

गड़चिरोली जैसे दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल जिले के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए राज्य मंत्री एवं जिले के सहपालक मंत्री एड. आशीष जयस्वाल के निरंतर प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है. उनके विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष, डा. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, ज्यूपिटर हॉस्पिटल, आरोग्यदूत फाउंडेशन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाल हृदय जांच शिविर में 346 बच्चों की अत्याधुनिक 2D-ईको जांच की गई. जांच के बाद 52 बच्चों की शीघ्र ही हृदय सर्जरी की जाएगी, जबकि 10 अन्य बच्चों को विस्तृत जांच के लिए मुंबई भेजा जाएगा. जांच के बाद आवश्यकता होने पर उनकी भी निःशुल्क सर्जरी की जाएगी. इस प्रकार कुल 62 बच्चों को इस विशेष स्वास्थ्य अभियान का लाभ मिलेगा. इन सभी 62 बच्चों के लिए गडचिरोली से मुंबई तक आने-जाने की यात्रा, अभिभावकों के साथ रहने एवं भोजन की व्यवस्था, अस्पताल में उपचार हृदय सर्जरी तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का पूरा खर्च निःशुल्क वहन किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह पहल किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. सहपालक मंत्री एड. आशीष जयस्वाल ने गड़चिरोली के जरूरतमंद बच्चों को मुंबई में उपलब्ध अत्याधुनिक हृदय चिकित्सा सुविधाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से डा. श्रीकांत शिंदे चिकित्सा सहायता कक्ष, ज्यूपिटर हॉस्पिटल, आरोग्यदूत फाउंडेशन व संबंधित संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया. उनके प्रयासों से बड़े स्तर पर बाल हृदय जांच शिविर आयोजित किया गया. जिन बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता है, उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा.

गैर-शैक्षणिक कार्य से करें मुक्त

मोर्चा से शिक्षकों का प्रलंबित मांगों की ओर ध्यानाकर्षण

संवाददाता / वर्धा

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के नेतृत्व में जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला. उल्लेखनिय यह कि, शिक्षकों ने स्कूल बंद आंदोलन कर मोर्चे में हिस्सा लिया था. मोर्चे की शुरुआत शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा परिसर से हुई. यहां बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्र हुए और मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालते हुए जिला

मुख्यालय पहुंचे. वहां प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की.

शिक्षक संगठनों ने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों से लंबे समय से अनेक गैर-शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं. जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. शिक्षकों का कहना है कि उन्हें मुख्यतः अध्यापन कार्य तक सीमित रखा जाए तथा अन्य विभागों के कार्यों से मुक्त किया जाए. मोर्चे के माध्यम से शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शिक्षकों के सेवा संरक्षण, एमआरपी शिक्षकों के संबंध में उचित निर्णय, बीएलओ सहित अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी, सेवा ज्येष्ठता से जुड़े मुद्दों का समाधान तथा अन्य लंबित प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया.

शिक्षक नेताओं ने कहा कि राज्यभर के शिक्षक लंबे समय से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं. लेकिन बार-बार निवेदन करने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है. इसके कारण शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. मोर्चे में जिले के विभिन्न तहसील से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. मोर्चे के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखा गया.

और तेज किया जाएगा राज्यव्यापी आंदोलन

जिला प्रशासन परिसर में हुई सभा में शिक्षक प्रतिनिधियों ने सरकार से चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया. तो राज्यव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी. शिक्षक संगठनों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार विद्यार्थियों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं का समाधान करेगी.

जिला योजना समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य बने अजयसिंह गौर

मराठी पत्रकार संघ ने किया सम्मान, संगठन को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने का लिया संकल्प

संवाददाता / तिरोडा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता, पूर्व नगराध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष तथा नगर परिषद सदस्य अजयसिंह गौर को गोंदिया जिला योजना समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर तालुका मराठी पत्रकार संघ की ओर से उनका पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर अजयसिंह गौर ने अपनी नियुक्ति के लिए वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद प्रफुल्लभाई पटेल तथा विधायक राजेंद्र जैन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर वे पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति में मिली यह जिम्मेदारी केवल एक पद नहीं, बल्कि जिले के विकास के लिए कार्य करने का महत्वपूर्ण अवसर है। वे जिले के सर्वांगीण विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने तथा विकास योजनाओं को गति देने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे।

अजयसिंह गौर ने यह भी कहा कि वे अपने नेताओं के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन विस्तार, जनसंपर्क और जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने विश्वास व्यक्त किया कि अजयसिंह गौर के अनुभव, सामाजिक सरोकार और विकासोन्मुख सोच का लाभ गोंदिया जिले को अवश्य मिलेगा। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के अनुभव के कारण जिला योजना समिति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी।

इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि किसी भी जिले के समग्र विकास में जिला योजना समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सामाजिक और राजनीतिक अनुभव रखने वाले प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को नई दिशा मिलने की अपेक्षा है। कार्यक्रम का समापन अजयसिंह गौर को शुभकामनाएं देते हुए इस विश्वास के साथ हुआ कि वे नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए गोंदिया जिले के विकास तथा संगठन की मजबूती के लिए उल्लेखनीय योगदान देंगे।

इटियाडोह बांध मार्ग के गहरे गड्ढों से हादसे की आशंका

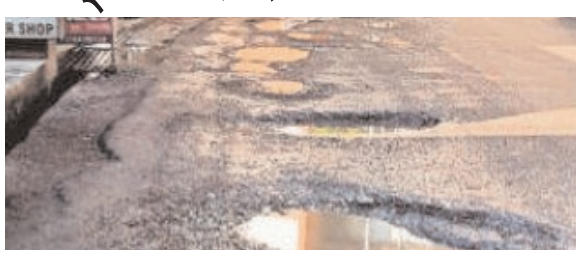

संवाददाता / नवेगांवबांध

गोठणगांव के इटियाडोह बांध की ओर जाने वाले मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ जाने से सड़क की दशा खराब हो गई है। इसके कारण इस सड़क से जाने वाले पर्यटकों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। समय रहते सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस मार्ग की मरम्मत की ओर ध्यान देकर मरम्मत करने की मांग पर्यटकों ने की है।

जिले के पर्यटन स्थलों में इटियाडोह बांध एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और इस स्थल को देखने के लिए रोज बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन, इस बांध की ओर गोठणगांव से जाने वाले मार्ग पर डामरीकरण उखड़कर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इसके कारण यहां आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस सड़क से केवल पर्यटक ही नहीं जाते, राजनीतिक नेता और वरिष्ठ अधिकारी भी जाते हैं। लेकिन, इस सड़क की मरम्मत की ओर उनका ध्यान न जाना पर्यटकों को आश्चर्यजनक लगता है। इस संबंध में कई पर्यटकों ने संबंधित विभाग से शिकायत कर मरम्मत की मांग की है। हर वर्ष सरकार सड़क विकास के लिए लाखों रुपये खर्च करती है।

जाम से शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा छुटकारा

संवाददाता / गोंदिया

शहर के अनेक मार्ग संकरे है। जहां से वाहन निकालना वाहन चालकों के लिए मुश्किल होता है। इससे आए दिन ऐसे मार्गों पर जाम की समस्या निर्माण हो रही है। शहर के अंडर ग्राउंड मार्ग, गोरेलाल चौक, श्री टॉकीज परिसर एवं अन्य क्षेत्र में आए दिन दोपहर एवं रात के समय यातायात जाम हो रहा है। इससे वाहन चालकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। शहर के छोटे व्यवसायी और कई प्रकार की दुकाने मार्ग से सटकर होने से यातायात जाम की समस्या निर्माण हो रही है। शहर

के एनएमडी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज आदि क्षेत्र में दोपहिया और चौपहिया वाहन आमने सामने आ जाते है। इतना ही नहीं तो अंडर ग्राउंड परिसर में भारी वाहनों के कारण यातायात जाम की समस्या ने वाहन चालकों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि शहर में आए दिन अनेक मार्ग पर जाम लग रहा है। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहने के बाद भी जाम से छुटकारा नहीं मिल रहा है। शहर में यातायात को संभालने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। यातायात बढ़ने से शहरवासियों व दुकानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बच्चों को भी स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। दुकानों के आगे अक्सर जाम लगने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। शहर के दुकानदारों के अनुसार कुछ जगहों में यातायात जाम होने से दुकानों के आगे गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। इससे ग्राहकों को दुकान में आने के लिए जगह नहीं बचती है। यही नहीं तो मार्ग पर नागरिकों द्वारा खड़े किए गए वाहन भी यातायात जाम का कारण बन रहे है। शहर के अनेक मार्ग पर दोपहिया वाहनों के साथ ही चौपहिया वाहनों को आड़ा-तिरछा खड़ा किया जा रहा है।

श्रमदान से १५ दिन में ग्रामीणों ने बढ़ा दी बांध की जलसंचय क्षमता

'नवेगांव बांध पैटर्न' राज्य के लिए बना रोल मॉडल

संवाददाता / नवेगांवबांध

महाराष्ट्र शासन के 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' अभियान को गति देने वाला नवेगांव बांध का जनसहभाग आधारित उपक्रम राज्य के लिए आदर्श बनता जा रहा है। मई-जून महीने के केवल 10 से 15 दिनों के श्रमदान से जलाशय की जलधारण क्षमता में कुल 1 करोड़ 60 लाख 65 हजार 178 लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। सिंचाई विभाग के उपविभागीय अधिकारी समीर बनसोडे के तकनीकी मार्गदर्शन में किसान, ट्रैक्टर मालिक, जेसीबी चालक

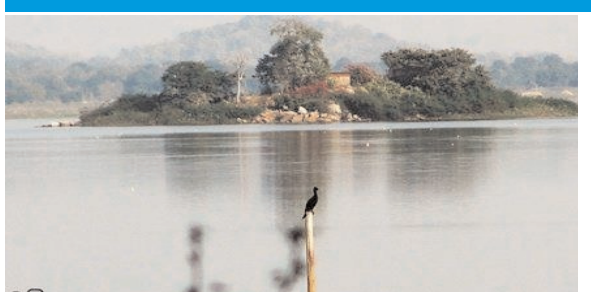

और ग्रामवासियों ने अपने खर्च से जलाशय की गाद निकालकर अपने खेतों में पहुंचाई। इससे जलाशय का प्राकृतिक गहराईकरण होने के साथ किसानों को उपजाऊ गाद का लाभ मिला। किसी विशेष शासकीय निधि की प्रतीक्षा किए बिना यह उपक्रम चलाया गया। इस प्रयोग से बारिश का अधिक पानी जलाशय में संचित होगा और आसपास के क्षेत्र की भूजलस्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। खेती के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध होने के साथ ही गर्मी के मौसम में वन्यजीवों की पानी की समस्या को भी राहत मिलेगी। कम खर्च, कम समय और जनसहभाग इस त्रिसूत्री पर आधारित 'नवेगांव बांध पैटर्न' को महाराष्ट्र में लागू करने की मांग नागरिक कर रहे हैं।

मार्ग पर बंधे मवेशियों से यातायात अवरुद्ध

गोंदिया : तहसील के गांवों में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और ग्राम पंचायत प्रशासन व जनप्रतिनिधि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. शहर की तरह ग्रामीण इलाकों में भी यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि गांवों में भी यातायात व्यवस्था प्रभावित है. गांव में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से सड़कें संकरी होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. इसी प्रकार गांव में अतिक्रमण का मामला काफी गंभीर होने के कारण ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता है. ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक अपने मवेशियों को छह फीट की सड़क पर बांध रहे हैं. जिससे यातायात में बाधा निर्माण हो रही है. वहीं सड़क पर जगह-जगह गंदगी नजर आ रही है. सड़कें कीचड़ से सनी होने के कारण कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है. हालांकि ग्राम पंचायत प्रशासन से कोई शिकायत नहीं करता. ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों की आंतरिक सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार हर साल निधि उपलब्ध करा रही है. कुछ स्थानों पर अच्छी सड़कें बनाई गईं. कुछ गांवों में जलापूर्ति योजना का काम हुआ है.

उड़ान पुल पर गड्ढे, सरिया और लोहे के ऐंगल उभरे

गड्ढों में पानी भर जाने से गहराई का अंदाजा नहीं लग रहा

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया शहर में विकास के नाम पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर प्रतिमा चौक से विशाल मेगा मार्ट तक उड़ान पुल का निर्माण वर्षों पहले किया गया था, जो अब वाहन चालकों की जान को दुश्मन बन गया है। उड़ान पुल के बीचों बीच गहरे गड्ढों का निर्माण हो गया है। सिर्फ गड्ढे ही नहीं बल्कि सरिया और लोहे के ऐंगल भी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं।

गौरतलब है कि गोंदिया-बालाघाट मार्ग को जोड़ने वाला रेलवे का पुराना पुल ब्रिटिश काल से शुरू था, जो जीर्ण अवस्था में

पहुंच जाने की वजह से उसे वर्ष 2022 को ढहा दिया गया। जिसके बाद एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए रेलवे के अंडर ग्राउंड मार्ग एवं नए उड़ान पुल पर यातायात काफी बढ़ गया है। शहर से इधर से उधर जाने के लिए यह दो दो ही मार्ग है। जिन पर भी वाहन चालक जान हथेली पर रख आवागमन करने को मजबूर है। इस उड़ान पुल के बीचों बीच गहरे गड्ढों का निर्माण हो चुका है, जिनकी गहराई बरसाती पानी भरने के बाद वाहन चालकों को पता नहीं चल पाती। ऐसे में वाहन पर सवार यात्री उछल रहे हैं। जिससे वाहन का संतुलन भी बिगड़ रहा है.

भारी वाहनों के नियमित आवागमन से ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग बदहाल

बिना अनुमति ट्रकों का परिवहन किए जाने का आरोप

संवाददाता / तिरोड़ा

तहसील के घाटों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। फिर भी राजस्व प्रशासन द्वारा ढुलमुल कार्रवाई कर शासन को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी ओर नागरिकों का कहना है कि तहसील में रेत तस्करों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्हें अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। तहसील में सड़कें खराब हैं क्योंकि परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन कर भारी वाहनों द्वारा रेत का परिवहन किया जा रहा है। लेकिन राजस्व और परिवहन विभाग द्वारा इन सभी मामलों की उपेक्षा की जाती है। जिला राजस्व प्रशासन ने तहसील में घाटों की नीलामी की। लेकिन, सरकार के फैसले की अवहेलना करते हुए निर्धारित घाटों के बजाय दूसरे स्थानों से अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में रेत की निकासी की जा रही है।

इतना ही नहीं, मशीनों के माध्यम से बेधड़क रेत उत्खनन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तहसील में भारी वाहनों का परिवहन किया जा रहा है। इससे गांवों की सड़कें खराब होने लगी हैं। भारी वाहनों के नियमित आवागमन से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अब दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। इस संबंध में अनेक ग्राम पंचायतों ने एकजुट होकर एक प्रस्ताव के जरिए तहसील प्रशासन से गांव के अंदर की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की है। फिर भी राजस्व प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। हालांकि यातायात नियमों का उल्लंघन कर भारी वाहनों द्वारा आवागमन किया जा रहा है, लेकिन परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए, तिरोड़ा तहसील निवासियों का आरोप है कि परिवहन और राजस्व विभाग की मिलीभगत से रेत परिवहनकर्ताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। तहसीलवासियों की मांग है कि जन प्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

शिक्षिका तलाश कर ले आयी सात बच्चे, वर्ना शाला को लग जाता ताला

शाला का अस्तित्व बचाए रखने शिक्षिका ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर

संवाददाता / गोंदिया

वर्तमान समय में जिला परिषद, नगर परिषद शालाओं का अस्तित्व विद्यार्थियों के अभाव में खतरे में आ गया है। पहले ही विद्यार्थियों की संख्या शून्य होने से गोंदिया जिप की 2 शालाओं को ताले लग गए हैं। ऐसे में गोंदिया नप की संत गाडगे महाराज मराठी प्राथमिक शाला का भी अस्तित्व खतरे में आ गया है, लेकिन इस शाला का अस्तित्व बचाने के लिए स्कूल में कॉन्वेट का प्रयोग शुरू किया है, वहीं कार्यरत शिक्षिका ने खोज-खोजकर 7 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाकर स्कूल को ताला लगाने से बचा लिया है। बता दें कि

गोंदिया नगर परिषद प्रशासन द्वारा 13 प्राइमरी शालाएं संचालित है, जहां पर लगभग 750 विद्यार्थी शिक्षा का पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन भौतिक, शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी तथा विभिन्न कारणों के कारण विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। वर्तमान समय में जिला परिषद व नगर परिषद शालाओं का अस्तित्व इसलिए खतरे में आ गया है कि विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले रहे है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन जिप की गोरेगांव की श्रीरामपुर तथा तिरोड़ा की बोंडरानी जिप स्कूलों को ताले लग गए। इसी श्रृंखला में गोंदिया नप की सूर्याटोला में स्थित संत गाडगे महाराज मराठी प्राथमिक शाला में भी प्रवेश संख्या शून्य थी, जिसे ताला लगना तय हो गया था, लेकिन कार्यरत शिक्षिका अश्विनी मिसाड ने अपने स्कूल का अस्तित्व बचाने के लिए एक अनोखी और प्रेरणादायी पहल की है। शिक्षिका ने विपरीत परिस्थितियों में घर-घर जाकर अभिभावकों को समझाकर खोज-खोजकर बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। अब स्कूल में कुल 7 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जिससे इस स्कूल को ताला लगने से बचा लिया गया है। इतना ही नहीं तो भविष्य में स्कूल का अस्तित्व बचाए रखने के लिए स्कूल में कॉन्वेट का प्रयोग शुरू कर लगभग 10 बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने भी शिक्षिका के इस अनोखे प्रयास की सराहना की और इसे अन्य शिक्षकों के लिए रोल मॉडल भी बताया है।

गर्म पानी गिरने से व्यक्ति झुलसा

गोंदिया : ग्राम खमारी निवासी शामराव देवाजी बनकर (52) के उपर ट्रैक्टर के रेडिएटर का गर्म पानी गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गया. उसे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती किया गया. शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

१५ खतरनाक पेड़ों की ओर अनदेखी

संवाददाता / गोंदिया

शहर के गणेशनगर क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े खतरनाक पेड़ों को हटाने की मांग नागरिकों ने करीब दस वर्ष पहले नगर परिषद से की थी. इसके लिए आवेदन भी दिया गया और कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप नागरिकों ने लगाया है. आखिरकार एक बड़ा पेड़ गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना के बाद नगर परिषद की अनदेखी पर लोगों में भारी नाराजगी है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों से क्षेत्रीय कार्यालयों और उद्यान विभाग को खतरनाक पेड़ों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उन पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जा रही है. नागरिकों का कहना है कि वे शहर को हराभरा बनाए रखने के लिए हमेशा वृक्ष संरक्षण का समर्थन करते हैं और अनावश्यक पेड़ कटाई का विरोध भी करते हैं. लेकिन जो पेड़ जर्जर, सूखे और लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं, उन्हें हटाने में प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है. जानकारी के अनुसार, वृक्ष गणना में शहर के 10 से 15 पेड़ों को खतरनाक श्रेणी में चिन्हित किया गया है. मानसून और तेज हवाओं के कारण पुराने व कमजोर पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ गया है. लेकिन, नगर परिषद के आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसे खतरनाक पेड़ों की स्पष्ट सूची उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है. कुकड़े ले-आउट, रिंग रोड, स्टेशन रोड, पुरानी नगर परिषद परिसर, सिविल लाइंस, जयस्तंभ चौक, रेलवे कॉलोनी, रावणवाड़ी-गोंदिया रोड, पुराने स्कूलों और शासकीय कार्यालयों के परिसर तथा नेहरू चौक क्षेत्र में कई पेड़ जर्जर अवस्था में हैं, जिससे यातायात और आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है.

कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर पर रिश्वतखोरी के आरोप

महिलाओं ने की पद से हटाने की मांग, अधिकारियों को सौंपे गए शिकायत पत्र

संवाददाता / सालेकसा

कारुटोला की सखी सीएमआरसी की कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर (सीसी) रोशनी बांगरे पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रिश्वतखोरी और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. नाराज महिलाओं ने बीडीएसपी दिव्या गणेश पटले के नेतृत्व में सखी सीएमआरसी की अध्यक्ष एवं सचिव को लिखित शिकायत सौंपकर रोशनी बांगरे को तत्काल पद से हटाने तथा पूरे

मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

शिकायत के अनुसार, महिलाओं का आरोप है कि सीआईएफ ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर प्रति एक लाख रु. के चेक पर 1,000 रु., जबकि पीजी समूह की ऋण फाइल पास कराने के लिए 4,000 रु. तक की अवैध वसूली की जाती है. इसके अलावा सहयोगिनियों के माध्यम से सीएमआरसी और माविम का नाम लेकर प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से 600 रु. लिए जाते हैं, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी जाती.

महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि शासन की धुआंरहित चूल्हा योजना के तहत निशुल्क वितरित किए जाने वाले प्रत्येक चूल्हे पर 100 रु. वसूले गए. वहीं ओएसएफ ऋण के लिए प्रति एक लाख रु. पर 2,400 रु. तथा प्रत्येक समूह से 1,500 रु. सेवा निधि के नाम पर जबरन वसूली करने का भी आरोप लगाया गया है. इस संबंध में महिलाओं ने पुलिस में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायतकर्ताओं को मानहानि का नोटिस

कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर रोशनी बांगरे ने शिकायत करने वाली महिलाओं को मानहानि का मुकदमा दायर करने संबंधी कानूनी नोटिस भेजा है. लेकिन शिकायतकर्ता महिलाओं का कहना है कि उनके पास लगाए गए आरोपों के पर्याप्त प्रमाण हैं. महिलाओं ने संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने, रोशनी बांगरे को पद से हटाकर न्याय दिलाने की मांग की है.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *

हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

वर्ष : 46 | अंक : 37 | गोंदिया, गुरूवार दि. 9 जुलाई 2026 | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 1.10 रू | Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

सड़कों पर प्लास्टिक कचरा

तिरोड़ा : सिंगल यूज प्लास्टिक पर शासन की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है यही नहीं सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी बैन है. इसका क्रियान्वयन करने के लिए शहर सहित समूचे जिले में प्रशासन की ओर से विविध दुकानदारों के खिलाफ प्लास्टिक थैलियां ग्राहकों को देने पर कार्रवाई की गई लेकिन अब कार्रवाई बंद होते ही शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिथीन का उपयोग बढ़ने लगा है. ठेला, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, दूध डेयरी, किराना दुकानों पर पॉलिथीन का उपयोग जमकर किया जा रहा है जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया है.

अब भी 55,000 वाहन बिना HSRP

नंबर प्लेट नहीं लगी तो होगी कार्रवाई

संवाददाता । गोंदिया

वाहनों में 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP' लगाना जरूरी कर दिया गया है. नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन बार-बार बढ़ाई गई. अब डेडलाइन भी खत्म हो गई है. इसके चलते उप प्रादेशिक परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है.

कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है. जिले में 55 हजार वाहनों में अभी तक 'HSRP' नंबर प्लेट नहीं लगी है. अब तक जिले में 45 वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है. वाहन धारकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई है. 1 जुलाई से नियमों का पालन न करने वाले वाहन धारकों पर कार्रवाई की जा रही है. इन वाहन धारकों के लिए कई जरूरी RTO सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है. अकेले गोंदिया जिले में ही 55 हजार से अधिक वाहन धारकों ने अभी तक अपने वाहनों पर यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है. ऐसे वाहन धारकों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जिले में कुल 1 लाख 78 हजार वाहन हैं, और अब तक 1 लाख 23 हजार वाहन धारकों ने HSRP नंबर प्लेट लगवा ली है. राज्य परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों को HSRP नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया था. इस कार्रवाई से बचने के लिए, वाहन धारक अधिकृत वेब पोर्टल पर

रजिस्ट्रेशन करें. अगर रसीद यातायात पुलिस को दिखाई जाती है, तो कार्रवाई नहीं की जाएगी.

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (HSRP) नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई थी. इसके बाद उप प्रादेशिक परिवहन विभाग सक्रीय हो गया है और अब तक विभाग ने हजारों वाहनों की जांच की है. जबकि इसमें दोषी पाए गए 45 वाहन धारकों पर जुर्माना लगाया गया है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाना जरूरी किया गया था. लेकिन वाहन धारको की बड़ी लापरवाही के कारण छह बार आगे बढ़ाकर 30 जून की डेडलाइन दी गई थी. साथ ही, इसके बाद कोई अंतिम तिथि न देते हुए बल्कि सीधे एक्शन लेने की चेतावनी दी गई थी.

बुराडे की जनसेवा को कभी नहीं भूलेगा सालेकसा

संवाददाता । सालेकसा

सालेकसा पुलिस थाने से नागपुर ग्रामीण में तबादला होने पर पुलिस निरीक्षक भूषण बुराडे का विभिन्न सामाजिक एवं पत्रकार संगठनों की ओर से नागरिक सम्मान किया गया. समारोह में वक्ताओं ने कहा कि बुराडे ने अपने लगभग तीन वर्ष के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार, शिक्षा और समाज सेवा से जोड़ने का उल्लेखनीय कार्य किया, जिसे सालेकसा हमेशा याद रखेगा.

कार्यक्रम का आयोजन पुलिस पटेल संगठन, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ, मोक्षधाम सेवा समिति, शांतता समिति, कुनबी समाज सेवा समिति तथा कमला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस थाना परिसर के सभागृह में किया गया. समारोह में बताया गया कि पुलिस निरीक्षक भूषण बुराडे के मार्गदर्शन में सालेकसा, बिजेपार व पिपरिया क्षेत्र में पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए. लगभग 100 युवाओं का पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों में चयन हुआ. साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए पुलिस और आमजन के बीच विश्वास का मजबूत संबंध स्थापित किया गया.

कार्यक्रम में पुलिस निरीक्षक भूषण बुराडे तथा उपनिरीक्षक मयूरी नागदेवे का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और सम्मानपत्र देकर अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर पुलिस पटेल संगठन अध्यक्ष लालचंद मचये, नगराध्यक्ष विजय फुंडे, उपाध्यक्ष कुंदन बहेकार, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ अध्यक्ष विजय मानकर, मोक्षधाम सेवा समिति के सुनील असाटी, कुणबी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष हेमने, गुणवंत बिसेन, गौरीशंकर भंडारकर समेत कई लोग उपस्थित थे. कार्यक्रम का शुभारंभ सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ. प्रस्तावना प्रा. गणेश भदाडे ने रखी. संचालन पुलिस पटेल विलास साखरे तथा आभार प्रदर्शन पवन पाथोडे ने किया.

समूचे जिले को आदिवासी जिला घोषित करने की मांग

संवाददाता । गोंदिया

महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी महासंघ ने राज्यसभा सांसद राजेंद्र जैन को ज्ञापन सौंपकर संपूर्ण गोंदिया जिले को आदिवासी जिला घोषित करने की मांग की है. महासंघ ने केंद्र एवं राज्य सरकार से इस संबंध में आवश्यक पहल करने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष इसकी अनुशंसा करने का आग्रह किया है.

महासंघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुछ जिलों को पहले ही आदिवासी जिला घोषित किया है. इसी तर्ज पर गोंदिया जिले को भी आदिवासी जिला घोषित किया जाना चाहिए. ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि गोंदिया जिला अपनी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत के कारण लंबे समय से आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. जिले के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करता है विशेष रूप से सालेकसा तहसील स्थित कचारगढ़ गुफा आदिवासी समाज के आदि धर्मस्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है और इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है. महासंघ का कहना है कि जिले में आदिवासी आबादी भी बड़ी संख्या में है. गोंदिया को आदिवासी जिला घोषित किए जाने से क्षेत्र के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा आदिवासी समाज को अधिक लाभ मिल सकेगा.

मानागढ़ जलाशय की नहरों का पानी सड़कों और बस्तियों में घुसा

16 उपनहरों में से केवल 4 की सफाई, मुख्य नहर में 2 किमी तक ही गाद निकाली

संवाददाता । सालेकसा

तहसील के मानागढ़ जलाशय की मुख्य नहर - उपनहरों की करीब 13 वर्षों बाद शुरू हुई सफाई और गाद निकालने का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून शुरू होने के बाद नहर की सफाई अधूरी रहने से बारिश का पानी नहर में सुचारू रूप से नहीं बह पा रहा है, जिसके कारण कई स्थानों पर बैक वाटर की स्थिति बन गई है।

स्थिति यह है कि नहर का पानी कई जगहों पर ऊपर से

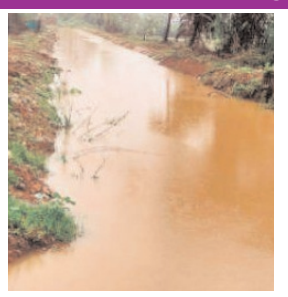

बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। वहीं कई स्थानों पर नहर से रिसने वाला पानी रिहायशी बस्तियों में जमा हो गया है। नागरिकों को जलभराव से राहत पाने के लिए स्वयं वाटर पंप लगाकर पानी की निकासी करनी पड़ रही है। इसके अलावा नहर से निकाली गई गाद भी कई जगह रास्तों पर ही पड़ी हुई है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने नहर सफाई कार्य को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं हो सका। वर्तमान में 16 उपनहरों में से केवल 4 की ही सफाई पूरी हुई है, जबकि मुख्य नहर में लगभग 2 किलोमीटर तक ही गाद निकाली जा सकी है।

मानागढ़ जलाशय से लगभग 1 हजार 525 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। गाद जमा होने और वर्षों से रखरखाव नहीं होने के कारण गोर्रे, सितेपाला, हल्बीटोला, मुरूमटोला, सालेकसा, आमगांव खुर्द, बोदलबोडी व दरबड़ा सहित कई गांवों तक पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा था। इसके चलते कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सिंचाई सुविधा से वंचित हो गया और वर्तमान में केवल 983 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई का लाभ मिल पा रहा है।

भोपाल स्टेशन पर बिछड़ी महिला के लिए सहारा बनी सालेकसा पुलिस, परिजनों तक पहुंचाया

संवाददाता । सालेकसा

जम्मू-कश्मीर से मजदूरी कर लौट रही एक छत्तीसगढ़ की महिला अपने पति से बिछड़कर सालेकसा पहुंच गई. सालेकसा पुलिस ने महिला को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचा दिया. छत्तीसगढ़ के बालोदाबाजार जिले के मंदईभाठा (सर्सिवा) गांव के रहने वाले धनाराम बुडहजात (40) और उनकी पत्नी सहोदरीबाई बुडहजात (36) काम की तलाश में जम्मू-कश्मीर गए थे. करीब चार-पांच महीने मजदूरी करने के बाद दोनों अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर पानी लेने उतरे पति ट्रेन छूट जाने के बाद वापस नहीं चढ़ सके और दोनों बिछड़ गए.

पति का इंतजार करती हुई सहोदरीबाई नागपुर तक पहुंच गईं, लेकिन पति का कोई पता नहीं चला. इसके बाद उन्होंने रायपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी, फिर भी पति नहीं मिले. रास्ते में यात्रियों की सलाह पर वह सालेकसा रेलवे स्टेशन पर उतरकर सीधे पुलिस थाने पहुंचीं और पूरी घटना बताई. सालेकसा पुलिस ने महिला की बात ध्यानपूर्वक सुनी, उनका हौंसला बढ़ाया और उनके गांव में मौजूद परिजनों से संपर्क किया. परिजन अगले दिन आने वाले थे, इसलिए पुलिस ने पास के वृद्धाश्रम में उनके रहने और भोजन की व्यवस्था कराई. 4 जुलाई की सुबह महिला का भतीजा और अन्य परिजन सालेकसा पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सहोदरीबाई को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

'स्कूल पूर्व तैयारी अभियान-2' से नए सत्र की हुई शुरुआत

संवाददाता / सोनपुरी

झालिया के पीएम श्री जिला परिषद हिंदी वरिष्ठ प्राथमिक आदर्श विद्यालय में 'स्कूल पूर्व तैयारी अभियान-2' के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश रहांगडाले ने की.

कार्यक्रम का उद्घाटन ग्राम पंचायत सरपंच कुंजन नवगड़े के हाथों हुआ. इस अवसर पर उपसरपंच ललितकुमार मच्छिरके, केंद्र प्रमुख एम.ए. घावले विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य विजय उके, भूमेश्वरी लांजेवार, ज्योति सोनवाने समेत बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित थे. कार्यक्रम की प्रस्तावना उच्च श्रेणी प्रधानाध्यापक रोशनलाल लिल्हारे ने रखी. संचालन स्नातक शिक्षक टी.आर. लिल्हारे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जे.आर. गणवीर ने किया. कार्यक्रम की सफलता के लिए सानिका बेलेकर, नताशा गजभिये, ए.सी. मच्छिरके, सीमा नागपुरे, विशाल दमाहे ने योगदान दिया. इस दौरान विद्यालय परिवार ने बताया कि 'स्कूल पूर्व तैयारी अभियान-2' का उद्देश्य बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र के लिए मानसिक व शैक्षणिक रूप से तैयार करना, उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है. कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व छात्रों के समग्र विकास का संदेश दिया.

गांवों में नालियों की सफाई नहीं, जहां हुई वहां मलबा नहीं उठाया

गोंदिया : कई गांवों नालियों की सफाई तो की गई, लेकिन निकाली गई गंदगी सड़क पर रख दी गई है। वहीं कुछ ग्राम पंचायतों ने नालियों की सफाई तक नहीं की है और ना ही पीने के पानी के जलस्त्रोंतों की सफाई की है। गोरेगांव तहसील स्वास्थ्य अधिकारी व तहसील नियंत्रण दल व गुट विकास अधिकारी पंचायत समिति ने 8 जुलाई को एक पत्र जारी कर सभी ग्राम पंचायतों को कहा गया है कि ग्रामों का निरीक्षण किया गया। जिसमें अधिकांश ग्रामों में नालियों की सफाई नहीं हुई है। गटर में पानी संग्रहित पाया गया। जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, उल्टी, दस्त जैसी जलजन्य संक्रमित बीमारियां होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।

नागरिकों का विरोध तेज, जिलाधीश को सौंपा मांगों का ज्ञापन

भूमिगत मार्ग नहीं, फ्लाईओवर बनाया जाए

संवाददाता । गोंदिया

गोंदिया चंद्रपुर रेलमार्ग पर कुंभारेनगर, लक्ष्मीनगर, सिग्नलटोली, आंबेडकर वार्ड और सावित्रीबाई फुले वार्ड क्षेत्र में रेलवे विभाग द्वारा बनाए जा रहे भूमिगत मार्ग (सबवे) का स्थानीय नागरिकों ने तीव्र विरोध किया है. नागरिकों ने इस स्थान पर भूमिगत मार्ग के बजाय फ्लाईओवर (उड्डानपुल) बनाने की मांग करते हुए सोमवार को जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश मंदार पत्की को ज्ञापन सौंपा. साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे तीव्र आंदोलन करेंगे.

नागरिकों का कहना है कि कुंभारेनगर, लक्ष्मीनगर, सिग्नलटोली और सावित्रीबाई फुले वार्ड का पूरा क्षेत्र मुंबई हावड़ा तथा गोंदिया चंद्रपुर रेलमार्ग से चारों ओर से घिरा हुआ है. वर्तमान में मौजूद भूमिगत मार्ग पूरी तरह अनुपयोगी साबित हो चुका है. बारिश के दिनों में इसमें पानी भर जाता है, गाद की सफाई नहीं होती, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था का अभाव रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं. रात के समय चोरी, लूटपाट और मारपीट जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसके कारण महिलाओं सहित सभी नागरिकों के लिए इस मार्ग से गुजरना असुरक्षित हो गया है. नागरिकों ने बताया कि यदि गोंदिया चंद्रपुर रेलमार्ग पर नया भूमिगत मार्ग बनाया गया तो पूरा इलाका दोनों ओर से बंद हो जाएगा. इसका सीधा असर आपातकालीन सेवाओं, स्कूल बसों, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और दैनिक जीवन पर पड़ेगा. आग लगने या अन्य आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.

साथ ही स्कूली बच्चों की आवाजाही भी प्रभावित होगी. नागरिकों ने मांग की कि रेलवे विभाग भूमिगत सबवे का निर्माण तत्काल रोककर वहां सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त फ्लाईओवर का निर्माण स्वीकृत करे, ताकि शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित व सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके.

सात दिनों बाद बारिश थमी, धान रोपाई-बुआई ने पकड़ी रफ्तार

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया जिले में जून माह बारिश का इंतजार करते हुए बीत गया। लेकिन दमदार बारिश नहीं हुई। जिसके चलते किसानों के साथ आम नागरिक भी चिंता में पड़ गए थे। लेकिन 1 जुलाई से जिले में धुआंधार बारिश शुरू हुई, जो लगातार 7 जुलाई तक चलती रही। इस दौरान कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश दर्ज की गई। इन 7 दिनों की अवधि में जिले में कुल मिलाकर

257.6 मिमी. औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि इस अवधि में सामान्य मानसून के दौरान 107.1 मिमी. बारिश अपेक्षित होती है। 8 जुलाई को बारिश का जोर कमजोर पड़ गया। लेकिन गोंदिया शहर सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की जानकारी मिली है।

अभी भी तिरोड़ा एवं अर्जुनी मोरगांव तहसील में अपेक्षित बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन धान उत्पादक किसानों ने अब बुआई का काम तेजी से शुरू कर दिया है और जिन स्थानों पर किसानों ने पहले से बुआई की थी वहां रोपाई का काम भी शुरू हो गया है।

११ को कलार समाज का होगा परिचय सम्मेलन

संवाददाता / गोंदिया

समस्त कलार समाज एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में उच्च शिक्षित विवाह योग्य युवक-युवतियों का परिचय परिचय बैठक समारोह का आयोजन 11 जुलाई को दोपहर 1 से 4 बजे तक रामदेव स्मृति भवन, बम्लेश्वरी कॉलोनी कॉम्पलेक्स, फुलचूर में किया गया है.

विवाह योग्य युवक-युवती के साथ ही पुनः विवाह करने इच्छुक विधुर, विधवा, तलाकसुदा, 35-40 उम्र पार, अपंग विकलांग, सफेद दाग, 10/12वीं कम पढ़े लिखे, किसान वर्ग, विशेष सादर आमंत्रित है. कार्यक्रम में रायपुर, बालाघाट, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, वर्धा, अमरावती, गड़चिरोली, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव से बहुतांश समाज बंधु पधार रहे हैं. सफलतार्थ एल.ए. खोब्रागडे, तीर्थराज उके, दिनेश फरकुंडे, नरेंद्र धुवारे, नीलिमा पशिने, सन्नी नशिने, सुनील उके, खेमराज देशमुख, सागर सोनवाने, दयाराम बन्सोड, पुरन मेश्राम, रवि रामटेक्कर, शाहू, मिलन रामटेक्कर सहित असंख्य समाज बांधव प्रयासरत है. समाजबंधुओं से उपस्थिति की अपील संचालक विजय कावडे ने की है.

बहे किसान का २ दिन बाद मिला शव

पुल के ऊपर से तेज गति से बह रहा था बाढ़ का पानी

संवाददाता / गोंदिया

आमगांव तहसील के आसोली गांव के समीप नाले पर बने पुल से तेज बहाव में बाइक सहित बह गए किसान का शव दो दिन की लगातार तलाश के बाद सोमवार सुबह बरामद किया गया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. ग्रामीणों ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुल पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग प्रशासन से की है. जानकारी के अनुसार, 5 जुलाई की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच आसोली गांव के पास नाले पर बने पुल के ऊपर से बारिश का पानी तेज गति से बह रहा था. इसी दौरान जांभुरटोला निवासी रूपचंद प्रेमीलाल बोपचे (43) खेती के कार्य से मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पुल पार करते समय उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वे बाइक सहित तेज पानी के बहाव में बह गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और संबंधित विभागों ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया. लेकिन नाले में पानी का बहाव अत्यधिक होने के कारण उन्हें

तुरंत तलाशना संभव नहीं हो सका. लगातार दो दिनों तक चले खोज अभियान के बाद मंगलवार, 7 जुलाई की सुबह करीब 7 से 7.30 बजे के बीच कुछ ग्रामीणों ने नाले में एक शव देखा. इसकी सूचना तुरंत परिजनों और पुलिस को दी गई.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आमगांव ग्रामीण अस्पताल भेज दिया. इस घटना के बाद आसोली क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उनका कहना है कि पुल की ऊंचाई कम है और दोनों ओर सुरक्षा रेलिंग नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल का पुनर्निर्माण कर उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, दोनों ओर मजबूत सुरक्षा रेलिंग लगाई जाए, बारिश के दौरान खतरे की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए जाएं तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों. ग्रामीणों ने मृतक रूपचंद बोपचे के परिवार को शासन की ओर से तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मांग की है.

विधानसभा में गूंजी विधायक विजय रहांगडले की आवाज

निमगांव (आंबेनाला) परियोजना के लिए एक माह में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन

संवाददाता । तिरोडा

वर्षों से लंबित निमगांव (आंबेनाला) मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर राज्य विधानसभा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रहांगडले ने लक्षवेधी सूचना के माध्यम से परियोजना के समक्ष सबसे बड़ी बाधा बने वन भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का मुद्दा प्रभावी ढंग से सदन में उठाया। इस पर संबंधित मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगामी एक माह के भीतर वन विचलन (डायवर्जन) की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि लंबे समय से सिंचाई सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे क्षेत्र के हजारों किसानों के लिए नई उम्मीद

लेकर आया है। निमगांव (आंबेनाला) मध्यम परियोजना वर्षों से विभिन्न प्रशासनिक एवं वन संबंधी औपचारिकताओं के कारण अटकी हुई है। यदि वन विचलन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होती है, तो परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

यह परियोजना तिरोड़ा-गोरेगांव क्षेत्र की कृषि व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्तमान में अधिकांश किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं, जिसके कारण अनियमित मानसून और सूखे जैसी परिस्थितियों में उत्पादन प्रभावित होता है। परियोजना के पूर्ण होने पर बड़ी संख्या में कृषि भूमि को सिंचाई का स्थायी स्रोत उपलब्ध होगा, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। विधानसभा में विधायक विजय रहांगडले ने इस विषय को किसानों के हित से जुड़ा बताते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। मंत्री द्वारा एक माह की समयसीमा के साथ दिया गया आश्वासन क्षेत्र के किसानों के लिए राहतभरी खबर माना जा रहा है। हालांकि अब किसानों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अपने आश्वासन को तय समय में धरातल पर कितना प्रभावी ढंग से लागू करती है। विधायक विजय रहांगडले ने कहा कि निमगांव (आंबेनाला) मध्यम परियोजना क्षेत्र के किसानों के भविष्य से जुड़ी है और इसे शीघ्र शुरू कराने के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना के साकार होने से सिंचाई क्षेत्र में व्यापक विस्तार होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। क्षेत्र के किसानों और नागरिकों ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाए जाने का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अब वर्षों से लंबित यह महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जल्द ही वास्तविकता का रूप लेगी।

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंः जेनिथचंद्र दोन्तुला

सीईओ ने कावराबांध पीएचसी का लिया जायजा

संवाददाता । गोदिया

बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में वातावरण बदलने से मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बीच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनिथचंद्र दोन्तुला ने मंगलवार को सालेकसा तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कावराबांध को आकस्मिक भेंट देकर स्वास्थ्य संस्था में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं का निरीक्षण किया। भेंट के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदरूनी व बाहरी परिसर की स्वच्छता, बाह्यरोगी सेवा (ओपीडी) के समय उपलब्ध हो रही मरीज सुविधाओं आदि का जायजा लिया।

उन्होंने इस दौरान कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशाला में की जा रही जांचों की जानकारी, एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह व रक्तचाप रोगियों की जानकारी, क्षेत्रीय कर्मचारियों की नियमित गांववार भेंट की योजना, पर्यवेक्षकों द्वारा उपकेंद्रों को भेंट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, औषधि भंडार, शासकीय निवासस्थान इ. विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुख्यालय में रहने, रोगी सुविधाएं गुणवत्तापूर्वक देने, वर्तमान में वर्षाकाल के दौरान कार्यक्षेत्र के नदी किनारे स्थित बाढ़ग्रस्त गांवों की गर्भवती माताओं को जटिलता होने से पहले ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करना, सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अच्छी प्रकार से किया जाए, कर्मचारियों द्वारा दौरा दैनिक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, स्वास्थ्य संस्था के रिकॉर्ड अपडेट कर मुख्यालय में रहने के निर्देश इस समय दिए गए। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कावराबांध की वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुषमा देशमुख, स्वास्थ्य सहायक प्रदीप कटरे व राठोड, फार्मासिस्ट संजय गुप्ता, प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश पारधी, महालंब की ज्योति दमाहे, स्वास्थ्य सहायिका मनीषा मेश्राम व संगीता बागड़े, स्वास्थ्य सेविका स्वाती टापरे, स्टाफ नर्स मोहन गिरी, समुदाय आसमुदाय स्वास्थ्य अधिकारी जीना बघेले, कनिष्ठ सहायक उमेश राऊत, परिचर हेमंत भैरव व बिसेन सफाईकर्मी ज्योति शेंदरे व ज्योति शिवणकर के साथ स्वास्थ्य संस्था के अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

डीएचओ ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण

संवाददाता । आमगांव

'मेरा गांव, स्वास्थ्य संपन्न गांव' अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अभिजीत गोल्हार ने आमगांव तहसील का दौरा कर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान डॉ. गोल्हार ने आमगांव ग्रामीण

अस्पताल, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बाम्हणी गांव तथा बनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया. उन्होंने पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए सीधे नागरिकों के घरों तक पहुंचकर अभियान के क्रियान्वयन की जानकारी ली. जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध दवाइयों, भर्ती मरीजों (आईपीडी), औषधि भंडार, टीकाकरण व्यवस्था, वैक्सीन की गुणवत्ता तथा मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की.

साथ ही कर्मचारियों के कार्यों और सरकारी अभिलेखों की भी जांच की. निरीक्षण के दौरान डीएचओ ने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा. इस अवसर पर तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रोशन राऊत, जिला विस्तार एवं मीडिया अधिकारी विजय आखाडे तथा बनगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉ. भूमेश पटले उपस्थित थे.

दूध व्यवसायियों की विशेष बैठक कल

संवाददाता । गोंदिया

जिले के सभी नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ व में मिलावट से मुक्त दूध की पूर्ति न हो इसके लिए जिलास्तरीय दूध मिलावट प्रतिबंधक समिति के निर्णय अनुसार प्रशासन ने सख्त कडे कदम उठाए हैं. इस अभियान के पहले चरण के तौर पर समिति के अध्यक्ष और अपर जिलाधीश की अध्यक्षता में जिले के सभी दूध और होटल व्यवसायिकों के लिए 7 जुलाई को दोपहर 3 से 4.30 बजे तक जिलाधीश कार्यालय के पहले माले पर पर समिति के कक्ष में विशेष समुपदेशन सभा रखी गई है.

मज़बूत शरीर के लिए नियमित व्यायाम ही असली निवेश : सचिन डोंगरवार

संवाददाता । नवेगांवबांध

स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम आवश्यक है। मजबूत शरीर के लिए नियमित व्यायाम ही असली निवेश है। ऐसा प्रतिपादन सहायक उपवन संरक्षक उद्घाटन के अवसर पर सचिन डोंगरवार ने किया है।

नवेगावबांध के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक टी-पॉइंट के पास स्थित डोंगरवार कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक फिटवीट व्यायामशाला का उद्घाटन सहायक उपवन संरक्षक सचिन डोंगरवार के हाथों किया गया। उस समय वे बोल रहे थे।

इस समय अर्जुनी मोरगाँव के वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोहुरे, चेतन नाकाड़े, रामदास बोरकर, हरिचंद्रलाड़े, दिनेश रामटेके, शुभम सांगोलकर, पंकज परशुरामकर, राहुल नरुले, सचिन सांगोळकर सहित अनेक मान्यवर एवं नागरिक अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फिटवीट यह फिटनेस और वाइटैलिटी की संकल्पनाओं पर आधारित है व्यायामशाला आधुनिक तथा यहाँ अत्याधुनिक व्यायाम उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

इस उपक्रम के कारण परिसर के युवकों एवं नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़कर मजबूत, तंदुरुस्त एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में मदद होगी, ऐसा विश्वास उपस्थित मान्यवरों ने व्यक्त किया।

जनहित के मुद्दे पर सक्रिय पहल रंग लाई, जलकुंभ-सालेबड़ी-मांडवी-मुंडीपार मार्ग की मरम्मत शुरू

संवाददाता । तिरोड़ा

क्षेत्र की जनता को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जिला परिषद सदस्य किरण पारधी के निरंतर प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली.

जलकुंभ-सालेबड़ी-मांडवी-मुंडीपार मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ-साथ गोंदिया कार्यालय में भी लगातार पत्राचार एवं अनुवर्ती कार्रवाई की। इसके अलावा तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजयभाऊ रहांगडाले को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई थी।जनप्रतिनिधियों की पहल और विभागीय स्तर पर हुए सकारात्मक प्रयासों का परिणाम यह रहा कि संबंधित मार्ग पर फिलहाल गड्ढों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को तत्काल राहत मिलने लगी है।इतना ही नहीं, इस मार्ग के स्थायी निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क को प्रशासनिक मंजूरी भी मिल चुकी है। वर्तमान में इसकी टेंडर प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि दीपावली अथवा दिसंबर-जनवरी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू होकर पूरा हो जाएगा।

सड़क बनने के बाद जलकुंभ, सालेबड़ी, मांडवी, मुंडीपार तथा आसपास के गांवों के हजारों नागरिकों को आवागमन की बेहतर और सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होगी।जिला परिषद सदस्य किरण पारधी ने कहा कि जनसमस्याओं को शासन और प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाकर उनका समाधान कराना ही जनप्रतिनिधि होने का वास्तविक दायित्व है। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपविभागीय अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहयोग और प्रशासन के समन्वय से क्षेत्र के विकास कार्य निरंतर गति पकड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने दोहराया कि 'जनता का विश्वास, विकास का संकल्प' उनकी कार्यशैली का मूल मंत्र है और क्षेत्र की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वे सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे।

महागांव-बंध्या मार्ग बदहाल

आवागमन में हो रही परेशानी, नागरिकों में रोष

संवाददाता । अर्जुनी मोर

महागांव से बंध्या तक लगभग पांच किमी. लंबाई वाली महत्वपूर्ण पक्की सड़क की स्थिति इस दयनीय हो गई है और बारिश के कारण पूरा मार्ग कीचड़मय बन गया है. सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए संबंधित विभाग द्वारा कुछ दिन पहले मुरुम डाला गया था. लेकिन लगातार हुई बारिश के कारण यह मुरुम बहकर सड़क पर कीचड़ का साम्राज्य बन चुका है. जिससे इस मार्ग पर यातायात खतरनाक बन गया है और नागरिकों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो रही है.

उल्लेखनीय है कि महागांव-बंध्या यह क्षेत्र का प्रमुख संपर्क मार्ग है और रोजाना सैकड़ों नागरिक, किसान, विद्यार्थी और विभिन्न कामों से आने-जाने वाले वाहन चालक इस सड़क का उपयोग करते हैं. लेकिन, हर जगह गहरे गड्ढे, कीचड़ और वाहनों के पहियों से बनी गहरी लकीरों के कारण दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय भारी कसरत करनी पड़ रही है. कई जगहों पर वाहन फिसलने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है. स्कूली विद्यार्थियों को रोज इस सड़क से स्कूल आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पैदल यात्रियों को भी कीचड़ से रास्ता निकालना पड़ रहा है और बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं तथा छोटे बच्चों की दुर्दशा हो रही है. बरसात में सड़क पर बने कीचड़ के कारण कुछ वाहनों के फंस जाने की घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसी जानकारी ग्रामवासियों ने दी. स्थानीय नागरिकों के अनुसार, केवल मुरूम डालकर गड्?ढों को भरने का अस्थायी उपाय निष्फल साबित हुआ है. हर साल बरसात में यही समस्या होने के कारण स्थायी समाधान के लिए कदम उठाना आवश्यक है. संबंधित विभाग ने गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण करके सड़क की पूरी मरम्मत करनी चाहिए, साथ ही पानी की सही निकासी होने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की मांग ग्रामीणों ने की है.

बच्चूभाऊ कडू के ५६ वें जन्मदिवस पर सेवा, संस्कार और पर्यावरण का संदेश

ई-लर्निंग सेंटर एवं वाचनालय का लोकार्पण
रक्तदान शिविर सहित अनेक जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित

संवाददाता / तिरोड़ा

प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू के 56वें जन्मदिवस के अवसर पर गोंदिया जिले में प्रहार संगठन द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े विविध जनहितकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा के प्रसार, समाजसेवा और मानवीय मूल्यों को समर्पित इन आयोजनों में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 56 फलदार पौधों का रोपण किया गया तथा दिव्यांगजनों को फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। किसानों के खेतों में पौधारोपण कर 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ' का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण

वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।इस अवसर पर स्वर्गीय इंदिराबाई बाबाराव कडू, स्वर्गीय महादेव परसराम हरडे तथा स्वर्गीय महादेव हानाजी भांडारकर की स्मृति में स्थापित वाचनालय एवं ई-लर्निंग सेंटर का लोकार्पण समाजसेविका सविताताई बेदरकर के करकमलों से फीता काटकर किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस केंद्र की स्थापना की गई है।कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों, समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा मेहनतकश किसानों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर समाजसेविका सविताताई बेदरकर ने अनाथ बच्चों के पालन-पोषण एवं सामाजिक सेवा के अपने अनुभव साझा करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। सुबह के सत्र में गुरुदेव सेवा भजन मंडल, नवेझरी द्वारा शिव मंदिर एवं हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना तथा भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं एवं नागरिकों के लिए भोजन प्रसाद का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में सविताताई बेदरकर, शिवसेना महिला जिलाध्यक्ष ज्योतीताई लिल्हारे, पंचायत समिति सदस्य वनिताताई जागेश्वर भांडारकर, सितेपार ग्राम पंचायत की सरपंच रजनीताई कुंभरे, समाजसेविका भेंडारकर ताई, नवेझरी के पुलिस पाटिल प्रकाश भांडारकर, सोनेखारी के पुलिस पाटिल अनमोल इळपाते, प्रहार के जिलाध्यक्ष जितेंद्र बावनकर, संगठन पदाधिकारी बिसेनजी, जिल्हा सचिव महेंद्र नंदागवली सहित बड़ी संख्या में किसान, दिव्यांगजन, महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक एवं प्रहार संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन प्रहार संगठन के गोंदिया जिला अध्यक्ष महेंद्र भांडारकर एवं जिला सचिव महेंद्र नंदागवली ने किया, जबकि मीडिया प्रमुख नरेंद्र वासनिक ने आभार व्यक्त किया। आयोजन की सफलता में उरकुडाजी उके, गोपाल शेंडे, रतन खुरसिंगे सहित संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और किसानों का उल्लेखनीय सहयोग रहा।

समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित इन कार्यक्रमों ने बच्चूभाऊ कडू के जन्मदिवस को केवल उत्सव तक सीमित न रखकर जनसेवा का प्रेरक अभियान बना दिया।

नहर की सफाई में देरी से बढ़ी परेशानी

संवाददाता / सालेकसा

तहसील के मानागढ़ जलाशय की मुख्य नहर व उप-नहरों की करीब 13 वर्षों बाद शुरू हुई सफाई और गाद निकालने का कार्य समय पर पूरा नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मानसून शुरू होने के बाद नहर की सफाई अधूरी रहने से बारिश का पानी नहर में सुचारू रूप से नहीं बह पा रहा है, जिसके कारण कई स्थानों पर बैक वाटर की स्थिति बन गई है.

स्थिति यह है कि नहर का पानी कई जगहों पर ऊपर से बहकर सड़क पर आ रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है. वहीं कई स्थानों पर नहर से रिसने वाला पानी रिहायशी बस्तियों में जमा हो गया है. स्थानीय नागरिकों को जलभराव से राहत पाने के लिए स्वयं वाटर पंप लगाकर पानी की निकासी करनी पड़ रही है. इसके अलावा नहर से निकाली गई गाद भी कई जगह रास्तों पर ही पड़ी हुई है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है.

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मानागढ़ नहर की सफाई

और गाद निकालने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार संबंधित विभाग को ज्ञापन दिए गए थे. इसके बाद शासन द्वारा कार्य के लिए निधि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन यदि सफाई अभियान समय रहते शुरू कर दिया जाता तो मानसून के दौरान नागरिकों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता.

जानकारी के अनुसार, मानागढ़ जलाशय की मुख्य नहर की पिछले 13 वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण उसमें बड़ी मात्रा में गाद जमा हो गई थी. इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और जलाशय का पानी कई गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा था. प्रशासन ने नहर सफाई कार्य को 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं हो सका. वर्तमान में 16 उप-नहरों में से केवल 4 की ही सफाई पूरी हुई है, जबकि मुख्य नहर में लगभग 2 किमी तक ही गाद निकाली जा सकी है.

मानागढ़ जलाशय से लगभग 1,525 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है. गाद जमा होने और वर्षों से रखरखाव नहीं होने के कारण गोरें, सितेपाला, हलबीटोला, मुरूमटोला, सालेकसा, आमगांव खुर्द, बोदलबोडी तथा दरबड़ा सहित कई गांवों तक पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा था. कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा सिंचाई सुविधा से वंचित हो गया और वर्तमान में केवल 983 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई का लाभ मिल पा रहा है.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *